लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

शनिवार, 23 अगस्त, 2025
वर्ष : 11 । अंक: 43
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

नहीं मांगता ऐ खुदा की जिंदगी सौ साल की दे! दे भले चंद लम्हों की, लेकिन कमाल की दें....

TODAY WEATHER

DAY 37° Hi | NIGHT 26° Low

संक्षेप

'न केवल ममतामय, बल्कि वैज्ञानिक तर्क...' आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का राहुल गांधी ने किया स्वागत

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत किया और कहा कि यह पशु कल्याण में संतुलन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के स्थानांतरण के अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा और उन्हें आश्रय स्थलों में नहीं रखा जाएगा, बशर्ते वे पागल या आक्रामक न हों। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूँ, क्योंकि यह पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह दृष्टिकोण न केवल दयालु है, बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को आठ हफ़्तों के भीतर आश्रय गृहों में पहुँचाने का आदेश दिया था, जिस पर कार्यकर्ताओं और पशु प्रेमियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अगले दिन, मामला सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय नई पीठ के पास भेज दिया गया, जिसने 14 अगस्त को मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

'कुत्ते हिंसक हैं या नहीं, कैसे तय होगा...', Stray Dogs पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेनका गांधी ने दिया ये सॉल्यूशन

नई दिल्ली, एजेंसी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को लेकर पशु अधिकार कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने स्वागत किया है। बता दें सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने आदेश दिया है कि शेल्टर होम भेजे गए सभी आवारा कुत्तों को छोड़ दिया जाए। मेनका गांधी ने कोर्ट के आदेश का समर्थन किया कि कुत्तों के लिए विशेष खाने की जगहें बनाई जाएं और इस बात पर जोर दिया कि 25 साल बाद पहली बार सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए संसद में 2500 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की है। मेनका गांधी ने कहा, मैं इस वैज्ञानिक फैसले से बहुत खुश हूं। कुत्तों के काटने की मुख्य वजह डर और जगह बदलना है। रेबीज से पीड़ित कुत्तों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने यह साफ नहीं किया कि आक्रामक कुत्ता कौन सा है, इसकी परिभाषा तय होनी चाहिए। उन्होंने बताया, हम यह तय करने का प्रयास करेंगे कि आक्रामक कुत्ते कौन हैं। कानून के अनुसार, इस मामले पर एक समिति गठित की जाती है, जो यह तय करती है कि किस तरह के व्यवहार को आक्रामक माना जाएगा। उन्होंने कहा, खाने की विशेष जगहें बनाना सही है। नगर निगम को ऐसी जगहों के लिए साइनबोर्ड भी लगाने होंगे। कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला पूरे देश पर लागू होगा। आदेश के मुताबिक, नगर निगमों को उचित एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर बनाना होगा। 25 साल में पहली बार सरकार ने संसद में कहा कि इस कार्यक्रम के लिए 2500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

पीएम हो या सीएम.. भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी, नए कानून पर गया में बोले पीएम मोदी

पटना, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आज 13 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने मगही भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जनता का सेवक बनकर काम करने में खुशी होती है। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लालटेन राज ने बिहार को लाल आतंक में जकड़ लिया था।

गयाजी में जनसभा में अपना संबोधन मगही भाषा में शुरू किया। उन्होंने कहा- हम अपने सब के अभिनंदन कर ही, मोक्ष आउ ज्ञान के धरती गया जी से हम सबके अभिनंदन कर ही।

जेल से नहीं चलेगी सरकार- पीएम

नए कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले उन्होंने कहा कि एक ऐसा कानून बन रहा है, जिसमें सीएम और पीएम सब दायरे में आएंगे। अगर 30 दिन के भीतर जमानत नहीं मिली तो 31 वें दिन कुर्सी छोड़नी होगी। जेल में रहकर सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी जेल जाएगा उसे कुर्सी छोड़नी ही होगी। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुझे जनता का सेवक बनकर उनके लिए काम करने में सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरा संकल्प है, जब तक हर किसी को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच में बीते 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। पीएम ने कहा कि केवल बिहार में 38 लाख से ज्यादा घर बने हैं। इसके साथ ही गयाजी में 2 लाख लोगों को घर मिला है। हमने सिर्फ चारदीवारी नहीं दी, बल्कि गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। जब तक हर गरीब को घर नहीं मिलता पीएम आवास योजना जारी रहेगी।

बिहार की धरती पर लिया गया संकल्प पूरा हुआ

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गया है। जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मारा गया, तब मैंने बिहार की इस धरती से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है कि बिहार की धरती पर लिया गया संकल्प पूरा हुआ है।" उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षानीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर, हमले कराके, कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों ना छिप जाएं, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके ही रहेंगी।

इस बार की दिवाली होगी खास- पीएम

इस बार बिहार में दीवाली और छठ पूजा की रौनक पहले से ज्यादा होगी, जो लोग अभी पीएम आवास योजना में छूट गए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास योजना तब तक जारी रहेगी, जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता है। उन्होंने कहा कि ये धरती, अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। यहां के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है।

जम्मू में 9 जगहों पर रेड, किस मामले में ED का यह एक्शन?

जम्मू। जम्मू में ईडी और एसीबी ने शुक्रवार को सुबह के समय कई लोकेशन पर छापेमारी की है। इनमें कैनाल रोड भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, ये छापे सुबह से ही जमीन घोटालों के मामले में किए जा रहे हैं, जिनमें राजस्व विभाग के अफसर और कुछ प्रभावशाली लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें पूर्व मंत्री का पीए भी शामिल है। ईडी जम्मू में जमीन हड़पने और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई 9 जगहों पर हो रही है। 8 लोकेशन जम्मू में है और 1 उधमपुर में है। यह कार्रवाई पटवारी प्रणव देव सिंह, पटवारी राहुल काई, नायब तहसीलदार अकील अहमद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ की जा रही है। मामला कस्टोडियन लैंड (वो जमीन जो पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थियों की थी) से जुड़ा हुआ है।

संसद भवन के परिसर में कूदा व्यक्ति, मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद भवन में एक बार फिर अवांछित व्यक्ति के प्रवेश करने से अफरा-तफरी मच गई। व्यक्ति संसद भवन के परिसर में दीवार फांदकर अंदर घुस गया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों की नजर पड़ते ही उसे पकड़ लिया गया। वह पेड़ पर चढ़कर दीवार से भवन में दाखिल हुआ था। घटना सुबह साढ़े 6 बजे की बताई जा रही है। घटना ऐसे समय घटी है, जब संसद का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति रेल भवन की ओर से दीवार से फांदकर संसद भवन के परिसर में आया था और नए संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। संसद का सुरक्षा बल आरोपी से पूछताछ के बाद उसे दिल्ली पुलिस को सौंपेगी। मामले में संसद की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। संसद में 13 दिसंबर, 2023 को शून्यकाल के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी अचानक दर्शक दीर्घा से लोकसभा सदन में कूद गए और बेंचों पर कूदते हुए गैस कनस्तर से पीले रंग की गैस उड़ा दी। उसी समय संसद के बाहर नीलम और अमोल शिंदे ने 'तानाशाही नहीं चलेगी' का नारा लगाकर रंगीन गैस उड़ाया। दिल्ली पुलिस ने 'मास्टरमाइंड' ललित झा, सागर शर्मा, मनोरंजन, नीलम आजाद, अमोल शिंदे और महेश को गिरफ्तार किया।

आवारा कुत्तों पर प्रीम कोर्ट ने निकाला बीच का रास्ता, लवर्स-डरने वालों को राहत

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर डॉग लवर और कुत्तों से परेशान लोगों की बीच टकराव काफी लंबे से पनप रहा था। दोनों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी कि आज कोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का इंतजार खत्म करते हुए शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा बीच का रास्ता निकाला जिससे न तो डॉग लवर्स की भावनाओं को ठेस पहुंची और न ही आवारा कुत्तों से परेशान लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज किया गया। आइए जानते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ऐसा क्या कहा, जिससे दोनों पक्ष के लोग संतुष्ट हो गए।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवारा कुत्तों पर अपने पुराने फैसले पर आंशिक रोक लगाते हुए उसमें संशोधन किया। कोर्ट ने अपने नए निर्देश में कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने को बैन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के खाने के लिए अलग भोजन स्थान बनाए जाएंगे क्योंकि कुत्ते काटने के अधिकतर मामले खाने की वजह से ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि वह सभी आवारा कुत्तों के लिए भोजन स्थल बनाएगा। कोर्ट ने डॉग लवर को चेतावनी देते हुए कहा कि भोजन स्थल के पास एक ऐसा नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें लिखा होगा की आवारा कुत्तों को केवल इन्हीं क्षेत्रों में ही खाना दिया जाएं। कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन करने वाले के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नसबंदी और टीकाकरण कर वापस छोड़ दिया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जो कुत्ते रेबीज से संक्रमित है या आक्रामक व्यवहार करते हैं उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा और इससे ग्रसित बाकी कुत्तों को भी शेल्टर होम में ही शिफ्ट किया जाएगा।

पुरे देश में लागू होगा फैसला

दिल्ली से शुरू हुआ मामला अब पूरे देश में फैल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग के सचिवों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया मांगी है। साथ ही कोर्ट ने उन सभी हाईकोर्ट से जानकारी मांगने का निर्देश दिया है, जहां आवारा कुत्तों के मुद्दे पर याचिकाएं लंबित हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे सभी मामले हाईकोर्ट को स्थानांतरित किए जाएं।

सभी नियमों का करना होगा पालन

दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा, जिसमें शामिल है: नगर निगम के अधिकारियों को पुराने फैसले के सभी निर्देशों का पालन करना होगा, सिवाय आवारा कुत्तों को न छोड़ने के निर्देशों को छोड़कर। कोर्ट ने कहा कि रेबीज या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को छोड़कर नगर निगम बाकी कुत्तों को छोड़ सकता है।

एसआईआर के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, पूछा- आप कर क्या रहे हैं?

बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर हैरानी जताई। दरअसल राजनीतिक पार्टियों ने मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नाम फिर से मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि 85 हजार नए मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए अभी तक सिर्फ दो आपत्ति दर्ज कराई गई हैं।

ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई कार, तीन की मौत, 3 घायल

नई दिल्ली/नोएडा। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल रोड पर अकबरपुर टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां खड़े ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे कार में सवार 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर थाना दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान तीन युवकों गौरव, लोकेश और गौतम की मृत्यु हो गई। जबकि ललित अरविंद और कुलदीप को भी चोटे आई हैं। जिनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने कार और ट्रक को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। नोएडा पुलिस के अनुसार ग्रेटर नोएडा के अकबरपुर टोल प्लाजा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल पर एक ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी। कार में छह व्यक्ति सवार थे, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां तीन की मौत हो थाना छांयसा, फरीदाबाद (हरियाणा) उम्र करीब 31 वर्ष को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। कार सवार हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे। मौके पर पहुंची दादरी पुलिस ने क्रेन और हाइड्रा की मदद से कार को काट-काटकर फंसे लोगों को बाहर निकाला।

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि मृतकों के शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं ट्रक और कार को कब्जें में लिया गया है साथ ही अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर यातायात सामान्य कर दिया गया है।

कानून-व्यवस्था और मनीषा केस पर हरियाणा विधानसभा में हंगामा, 30 मिनट के लिए सदन स्थगित

नई दिल्ली, एजेंसी। हरियाणा विधानसभा में हंगामा जारी है. सदन की कार्यवाही तीसरी बार आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है।कांग्रेस विधायक इस जिद पर अड़े हैं कि प्रश्नकाल को स्थगित करके पहले प्रदेश की कानून-व्यवस्था और भिवानी में प्ले स्कूल टीचर के कथित हत्याकांड के मामले को लेकर चर्चा हो और उसके बाद ही सदन की कार्रवाई आगे बढ़े।स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि उस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी लेकिन पहले सदन की कार्यवाही चलने दी जाए।बार-बार कांग्रेस विधायकों के वेल में आने और नारेबाजी और हंगामा करने के कारण कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। हरियाणा विधानसभा में लगातार जारी हंगामे को देखते हुए विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है।

मतदाता सूची विवाद पर बोली कांग्रेस- लोकतंत्र बच गया, बिहार SIR पर 'सुप्रीम' फैसले का किया स्वागत

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने (एसआईआर मुद्दे) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र पर हुए एक कठोर हमले से देश को बचाने वाला है और चुनाव आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली को पूरी तरह उजागर कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि काटे गए मतदाताओं की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। इसके साथ ही सूची के साथ-साथ नाम काटने की वजह भी बताई जाए। कोर्ट ने या भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वे आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर दिखाकर मतदान कर सकें। आज अदालत ने अपने ही आदेश को दोहराते हुए साफ कहा कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को वैध पहचान पत्र मानना ही होगा।

कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को सुरक्षित किया है। चुनाव आयोग ने अब तक बाधा डालने वाली और मतदाताओं के अधिकारों के खिलाफ काम करने वाली भूमिका निभाई थी। लेकिन अब अदालत ने राजनीतिक दलों को भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करने का रास्ता खोल दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है।' कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब उन्हें एक लागू होने योग्य अधिकार मिल गया है जिसे चुनाव आयोग अनदेखा नहीं कर सकता।

बिहार का सियासी माहौल गर्म

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर 'वोट चोरी अभियान' चलाने के आरोपों को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है. विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर रही है। इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके बिहार के लोगों से उनका मताधिकार छीनने की अनुमति नहीं देगा। कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के पांचवें दिन मुंगेर में भारी बारिश के बीच एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि 'वोट चोरी' संविधान पर हमला है।

चुनाव आयोग पर तीखा हमला

कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा- 'आज चुनाव आयोग पूरी तरह बेनकाब और बदनाम हो चुका है। उसके पीछे के 'जी-2 कठपुतली संचालक' भी पूरी तरह पराजित हो गए हैं।'

सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर से हंगामा, गांधीनगर में हुई नारेबाजी; पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर से हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि अशोक बाजार गांधी नगर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थोक रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित वस्त्रिका 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थीं। एक शख्स यहां नारेबाजी कर हंगामा कर रहा था। जिसे बैरिकेडिंग के बाहर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं, जानकारी मिली है कि एक अन्य शख्स को भी हंगामा करने के संदेह में पकड़ा गया है।

जनसुनवाई में मुख्यमंत्री पर हुए हमले के बाद रेखा गुप्ता पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकली थीं। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक अरविंद सिंह लवली, पार्षद और गांधीनगर मार्केट के तमाम व्यापारी मौजूद रहे। इस हंगामे से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह हमला हुआ था। दिल्ली सीएम हाउस में यह घटना घटी। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री रेखा साप्ताहिक जनसुनवाई कर रहीं थीं। इसी दौरान करीब 40 साल के एक शख्स ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी हमलावर को पकड़ लिया। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मुख्यमंत्री पर गुजरात के राजकोट निवासी राजेश खिमजी ने उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर हमला किया था।

शीतगृहों से आलू निकासी की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

किसानों को आलू विक्रय हेतु यथा आवश्यक मार्केट उपलब्ध कराने व खाद आपूर्ति पर भी हुई चर्चा

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शीतगृहों से आलू निकासी की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन,उप निदेशक उद्यान,शीतगृह स्वामियों, मंडी सचिव एवं किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2025 की आलू भण्डारण स्थिति, वर्तमान निकासी दर, मंडी भाव तथा किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान वर्ष 2025 में जनपद के 77 निजी शीतगृहों में कुल 7,69,226 मीट्रिक टन आलू भण्डारित हुआ था।जिले के 90 प्रतिशत से अधिक किसान आलू की खेती करते हैं और अधिकांश उत्पादन बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम राज्यों में भेजा जाता है। गत वर्ष अगस्त माह में आलू की निकासी दर 33 प्रतिशत रही थी, जबकि इस वर्ष अगस्त 2025 में निकासी घटकर लगभग 25.40 प्रतिशत पर आ गई है। जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने मंडी सचिव व जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए कि किसानों को यथासंभव मार्केट उपलब्ध कराया जाए और शीतगृह स्वामियों को भी किसानों के हित में सहयोग हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने किसान यूनियन पदाधिकारियों व किसानों से संवाद कर जनपद में खाद की उपलब्धता पर भी जानकारी ली। किसानों ने बताया कि अब समितियों के माध्यम से खाद पहले की अपेक्षा अब सुगमता से किसानों को प्राप्त हो रही है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अन्ना सुदन, उप निदेशक उद्यान श्रीमती गीता त्रिवेदी, जिला उद्यान अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पशु चिकित्सालय, पर नि :शुल्क एग कार्ट का वितरण किया गया

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। अंगद कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद की गरिमामयी उपस्थिति में नेशनल एग को-आर्डिनेशन समिति (एन0ई0सी0सी0) द्वारा पशुपालन विभाग के सहयोग से पोल्ट्री व्यवसाय की वृद्धि एवं स्वरोजगार हेतु पशु चिकित्सालय, पर निःशुल्क एग कार्ट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जनपद के 10 लाभार्थियों को एग कार्ट का वितरण किया गया। कार्यक्रम के शुभारम्भ के अवसर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 अतुल कुमार अवस्थी द्वारा माननीय एम0एल0सी0 साहब को बुके देकर स्वागत किया गया। माननीय सदस्य विधान परिषद श्री अंगद कुमार सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित पशुपालकों को पशुपालन विभाग की योजनाओं में सहभागिता करने एवं स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया गया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अण्डा प्रोटीन का एक अच्छा एवं सस्ता श्रोत है तथा अण्डे खाने से शरीर को उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन भी पाए जाते है। साथ ही इसमें विटामिन ए, डी, बी कॉम्प्लेक्स, और कोलीन जैस पोषण तत्व होते है। कुपोषण को दूर करने में अण्डे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अण्डे में पाये जाने वाले पोषण तत्व वजन और बेलीफैट को कम करने में मददगार होते है। कार्यक्रम में माननीय एम0एल0सी0 साहब द्वारा लाभार्थियों से औपचारिक परिचर प्राप्त किया गया तथा लाभार्थी जियालाल पुत्र मथुरा प्रसाद, राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द्र, श्री देवीदीन पुत्र श्री फूलचन्द्र, सुभाष पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद, राकेश कुमार पुत्र श्री सहजराम, हरिओम पुत्र श्री रामशंकर, श्री रामनेवाज पुत्र श्री रामस्वरूप, श्री विनोद पुत्र कृष्णा, मनोज कुमार पुत्र श्री रामगोपाल एवं श्री बलदेव पुत्र श्री मोहन लाल को एग कार्ट वितरित किया गया।

एसपी ने लिया साप्ताहिक परेड की सलामी परेड व पुलिस लाइन का किया निरीक्षण

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक, अर्पित विजयवर्गीय द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित परेड ग्राउण्ड में शुक्रवार की परेड की सलामी ली गई, तत्पश्चात परेड में उपस्थित समस्त पुलिसकर्मियों को शारीरिक व मानसिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ कराई गयी व पुलिसकर्मियों का टर्न आउट चेक करते हुए अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने हेतु ड्रिल की कार्यवाही कराई गयी। पुलिस अधीक्षक द्वारा यूपी 112 पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर संबंधित पीआरवी के मानक के अनुसार हेड लाइट, हूटर, इंडिकेटर फर्स्ट एड किट आदि समस्त आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने व उनके सुव्यवस्थित रखरखाव व साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात रिक्रूट आरक्षियों की कैंटीन, सलून, क्लास रूम, बैरक, व्यायामशाला, शस्त्रागार, परिवहन शाखा, आवासीय परिसर एवं पुलिस लाइन भोजनालय में भोजन की गुणवत्ता व साफ सफाई आदि का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। आदेश कक्ष में विभिन्न रजिस्टरों एवं अभिलेखों को चेक कर अद्यावधिक रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन श्री संगम कुमार, प्रतिसार निरीक्षक राजेश कुमार आदि अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

टीचर बने ठेकेदार, बच्चों को बनाया मजदूर फावड़े से बना रहे मसाला, कब होगी कार्रवाई ?

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिन हाथों में पेन किताब कॉपी होनी चाहिए, उन हाथों में शिक्षकों ने फावड़ा पकड़ा दिया। प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है, लेकिन अधिकारी आंखों में पट्टी बांधकर, वायरल वीडियो पर करवाई करने से बच रहे है। पूरी घटना सचेण्डी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय द्वितीय की है।

इस वीडियो में मासूम बच्चों से फावड़ा उठवाकर काम करवाया जा रहा है। वीडियो सामने आते ही स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चों के परिजनों में आक्रोश है। उनका कहना है शिक्षा विभाग में शिकायत करके ऐसे शिक्षकों के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई करेंगे।

स्कूल प्रशासन पर उठे सवाल

इन दिनों बारिश के मौसम में प्राथमिक सरकारी स्कूल में जमीन पक्की ना होने के चलते जल भराव हो रहा था। इस पर विभाग की ओर से इटरलॉकिंग टाइल्स भेजकर काम करवाने को कहा गया। लेकिन जो काम मजदूरों से कराया जाना था, उस काम को स्कूल के बच्चों से कराया जाने लगा। अब मजदूरों का बच्चों से कराया जाएगा तो जिम्मेदारों पर सवाल खड़े होना लाजमी है।

बच्चों के हांथ में फावड़ा

जहां प्राइवेट स्कूलो में बच्चों को बारिश से बचाने के लिए कक्षा में व्यवस्था की जाती है वहीं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से बारिश में बालू-सीमेंट का मसाला बनवाया जा रहा है। इस डिजिटल भारत में शिक्षा के बढ़ते स्तर की सच्चाई समाज के सामने है। जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए थी उनके हाथों में प्रधानाचार्य महोदया ने फावड़ा, तसला और इंटर लॉकिंग टाइल्स थमां दिया है।

परिजनों ने की कार्रवाई की मांग

परिजन कहते हैं कि बच्चों का भविष्य उलझा हुआ है। गरीब का बच्चा शिक्षा से दूर होता जा रहा है। कानपुर प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को शिक्षा देने के बजाय उनसे मजदूरी कराया जा रहा है। बाल मजदूरी का वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बच्चे इंटरलॉकिंग उठाकर एक महिला कर्मचारी के साथ काम कर रहे हैं। स्कूल के प्रांगण में पानी भरा हुआ है कुछ बच्चे फावड़ा लेकर सीमेंट और बालू के मिश्रण को फैला रहे हैं।

अब इन गरीब समाज के बच्चों के लिए सरकारी सुविधाओं से वंचित कर उनसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है। बच्चो को इस तरह से देख परिवार के लोगों में आक्रोश है। लोग स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाल ही में कानपुर देहात के स्कूल में भी बच्चों से काम करने पर कुछ बच्चों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिसके बाद प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।

किसानों की आय वृद्धि व जल संरक्षण को लेकर डी0एम0 ने की दो महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यान विभाग से संबंधित दो महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इन बैठकों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन तथा पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रो इरीगेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएँ किसानों की आय दोगुनी करने, उन्नत खेती को प्रोत्साहित करने और जल संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों तक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जाए और उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन समय से उपलब्ध हो। बैठक में बताया गया कि इस मिशन के तहत फल, सब्ज़ी, फूल एवं मसालों एवम मशरूम की खेती के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इसके तहत जिले के किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध, उन्नत किस्मों के बीज तथा आधुनिक खेती तकनीकों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों को अधिक लाभ भी मिलेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण व गोष्ठियों का आयोजन किसान दिवस के अवसर पर व ब्लॉकों में नियमित रूप से किया जाए। दूसरी बैठक में माइक्रो इरीगेशन (टपक सिंचाई/स्प्रिंकलर) योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि यह तकनीक जल संरक्षण की दिशा में कारगर है, जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव हो पाती है।

ज्यादा कमाई का लालच देकर दुबई भेजा, वहां शेख ने रेगिस्तान में बंधक बनाया

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

कानपुर। विदेश में नौकरी और मोटी कमाई का सपना दिखाकर खुद दोस्त ने ठग के माध्यम से कानपुर के एक युवक को सऊदी अरब भेज दिया, जहां उसको बंधक बना लिया गया। वहां 19 दिनों तक उसे भूखा-प्यासा रखकर जबरन काम कराया गया और तरह-तरह की यातनाएं दी गईं। किसी तरह जान बचाकर भागा पीड़ित एंबेसी पहुंचा और फिर स्वदेश लौटा।

कानपुर आने के बाद युवक ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसके बाद नौबस्ता थाने में मामला दर्ज किया गया है। नौबस्ता आवास विकास निवासी आरिफ अंसारी मजदूरी कर परिवार का खर्च उठाता था। पिता आलमगीर और मां की तबीयत खराब रहने के कारण उस पर घर की जिम्मेदारी थी। इस बीच दोस्त दिलशाद ने उसकी मुलाकात रनियां निवासी शाहरुख से कराई। शाहरुख ने विदेश में नौकरी और मोटी आमदनी का लालच देकर आरिफ को बाहर भेजने का भरोसा दिलाया। आरिफ ने विदेश जाने के लिए अपनी बाइक बेचकर पैसा जुटाया। आरोप है कि शाहरुख ने उससे 1.50 लाख रुपए लिए और फतेहपुर के छुरी गांव निवासी अयाज से संपर्क कराया। अयाज ने पासपोर्ट की कॉपी और 50 हजार रुपए और मांगे। कहा गया कि 15-20 दिन में सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। इसतके बाद तय समय पर आरिफ मुंबई पहुंचा तो अयाज ने उससे पैसे लेकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए और भरोसा दिलाया कि सऊदी अरब पहुंचते ही उसे वहां की करेंसी मिल जाएगी। अप्रैल में आरिफ सऊदी अरब पहुंचा। वहां एक एजेंट उसे लेकर रेगिस्तान में बने एक तंबू पर छोड़ गया। कुछ देर बाद एक शेख आया, जिसने आरिफ का मोबाइल तोड़ दिया और उसे बंधक बना लिया।

एंबेसी अधिकारियों ने की मदद

इसके बाद शुरू हुआ अमानवीय व्यवहार। आरिफ को 19 दिनों तक भूखा-प्यासा रखा गया और जबरन काम कराया गया। विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया। आरिफ ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से भागने का रास्ता निकाला। शेख की नजर बचाकर वह वहां से निकल सका और भारतीय दूतावास पहुंचा। एंबेसी अधिकारियों की मदद से उसने परिजनों से संपर्क साधा और स्वदेश लौटने की प्रक्रिया पूरी की। आरिफ 30 जुलाई को कानपुर वापस आया। इसके बाद उसने पुलिस कमिश्नर को पूरी आपबीती सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए नौबस्ता थाने में शाहरुख, अयाज और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।

कैसे भरोसा करें सरकार? घर से स्कूल ले जाने वाले 500 से अधिक स्कूलों के ड्राइवर पर हैं क्रिमिनल केस

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चल रही मिशन भरोसा परियोजना की समीक्षा में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्कूली वाहनों के 500 से अधिक चालकों के चरित्र सत्यापन में आपराधिक प्रवृत्ति सामने आई है, जिसके चलते उनके प्रमाणपत्र रोक दिए गए हैं। यह जानकारी मंडलायुक्त डॉ। रोशन जैकब ने गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में दी।

उन्होंने सख्ती से कहा कि बिना चरित्र सत्यापन के कोई भी चालक स्कूली वाहन नहीं चला सकेगा। लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित भरोसा पोर्टल पर अब तक 5200 स्कूली वाहनों, 2545 चालकों, 197 कंडक्टरों व हेल्परों और 470 स्कूलों का पंजीकरण किया जा चुका है। इनमें से 1000 चालकों का चरित्र सत्यापन और ड्राइविंग लाइसेंस जांच पूरी होने के बाद उन्हें मिशन भरोसा स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है।

थानावार सत्यापन सूची तैयार करने का निर्देश

मंडलायुक्त ने शेष चालकों का सत्यापन शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। डॉ। जैकब ने पुलिस और मिशन भरोसा टीम को निर्देश दिया कि सत्यापन के लिए प्रतीक्षारत चालकों की थानावार सूची तैयार कर पुलिस को भेजी जाए। इससे यूपी कॉप ऐप पर प्राप्त आवेदनों को बच्चों की सुरक्षा से जोड़कर प्राथमिकता के साथ सत्यापन हो सकेगा।

समीक्षा बैठक में जॉइंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) बल्लू कुमार, नगर आयुक्त गौरव कुमार, आरटीओ प्रवर्तन प्रभात कुमार पांडेय, जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन प्रदीप कुमार सिंह और मिशन भरोसा निदेशक आलोक सिंह शामिल थे। बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदममिशन भरोसा परियोजना का मकसद स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।

स्कूली वाहन प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता आएगी

इस पहल के तहत चालकों और वाहनों का कड़ाई से सत्यापन किया जा रहा है, ताकि अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में विश्वास बना रहे। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यह कदम न केवल बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि स्कूली वाहन प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करेगा।

यूपी में आसानी से मिल जाएगा पुश्तैनी जमीन का नक्शा, नहीं काटने पड़ेंगे तहसील के चक्कर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

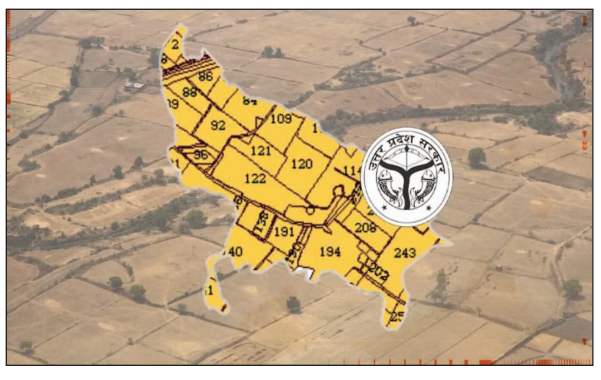

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में अब पुश्तैनी जमीन के भू-मानचित्र (नक्शे) प्राप्त करना आसान हो जाएगा। बार-बार तहसील और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व विभाग ने इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत तहसील स्तर पर भू-मानचित्र उपलब्ध न होने या जीर्ण-शीर्ण होने की स्थिति में उसे नए सिरे से तैयार कर सुरक्षित रखा जाएगा।

साथ ही, आवेदकों को इसकी कॉपी आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, एसवीएस रंगाराव ने सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि तहसील, जिला स्तर और राजस्व अभिलेखागार के साथ-साथ बंदोबस्त अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी के कार्यालयों में भू-मानचित्रों की खोजबीन कर उन्हें संग्रहीत और सुरक्षित किया जाए।

प्रयागराज से मिलेगी मदद

अगर कोई नक्शा नष्ट हो गया है, अनुपलब्ध है या खराब हालत में है, तो इसके कारणों की जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी। जांच के बाद संबंधित रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजी जाएगी। यदि तहसील, जिला या राजस्व परिषद स्तर पर भी भू-मानचित्र उपलब्ध नहीं है, तो निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज से संपर्क किया जाएगा। वहां से नक्शा प्राप्त करने का प्रयास होगा।

पुश्तैनी जमीन की सटीक जानकारी मिलेगी

अगर वहां भी नक्शा उपलब्ध नहीं हुआ, तो संबंधित राजस्व ग्रामों के भू-मानचित्र नए सिरे से तैयार कराए जाएंगे। इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर आवेदकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से आम नागरिकों को अपनी पुश्तैनी जमीन की सटीक जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। नए और सुरक्षित भू-मानचित्रों की कॉपी आवेदन करने पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे जमीन संबंधी विवादों का निपटारा करने में भी मदद मिलेगी। यह कदम खासकर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा, जो अपनी पैतृक संपत्ति की जानकारी जुटाने के लिए लंबे समय से परेशान थे।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड मण्डल अनुश्रवण पुस्तिका में परिलक्षित राजस्व कार्यो की मण्डलायुक्त ने की समीक्षा

» मण्डल के तीनो जपनद को विभिन्न 32 योजनाओं में ए श्रेणी प्राप्त

आर्यावर्त संवाददाता

मीरजापुर। मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल बालकृष्ण त्रिपाठी ने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में कर करेत्तर, राजस्व वसूली से सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री डैशबोर्ड अनुश्रवण पुस्तिका में परिलक्षित राजस्व कार्यो की रैंकिंग श्रेणी के अनुसार समीक्षा कर बी0 व सी0 श्रेणी प्राप्त करने वालो विभागो पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार लाने का निर्देश दिया। कर एवं करेत्तर, मुख्य देय, विविध देय तथा अन्य राजस्व से सम्बन्धित विभिन्न 32 योजनाओं में मण्डल को ए श्रेणी प्राप्त हुआ हैं। ए श्रेणी प्राप्त करने वाले योजनाओं में राइट आफ वे, उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य, पेट्रोल पम्पों का सत्यापन मुद्राकंन, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मण्डी आय, मण्डी आवक, औषधि विक्रय लाइसेंस, संकलित नमूना एवं कृत कार्यवाही औषधि, संकलित नमूना एवं कृत कार्यवाही खाद्य, अमृत-2, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आई0एम0एम0एस0एस0 के अनुसार प्रर्वतन कार्य, एल0ओ0आई0 के लिए आनलाइन आवेदन, प्रर्वतन कार्य, कृषि भूमि से गैर कृषि, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ई खसरा खरीफ, ई खसरा रबी, एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन, एंटी भू माफिया, जाति प्रमाण पत्र, निर्विवाद उत्तराधिकार, भूलेख, साल्वेंसी सर्टिफिकेट, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, भूतपूर्व सैनिको के परिचय हेतु आनलाइन सेवाएं को ए श्रेणी प्राप्त हुआ हैं। उन्होंने अन्य विभागो को प्रगति में अपेक्षित सुधार लाते हुए अगस्त माह की समीक्षा रिपोर्ट ए श्रेणी लाना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा के दौरान जनपद सोनभद्र में आधार सीडिंग शत प्रतिशत न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल शत प्रतिशत आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि दुकानों, रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाकर खाद्य पदार्थो की सैम्पलिंग इकट्ठा करते हुए कृत कार्यवाही करें। उन्होंने पूर्व में जांच किए सैम्पल में क्या कार्यवाही की गई के बारे में विस्तृत जानकारी ली। बैठक में उद्योग विभाग, आबकारी, मण्डी परिषद, कृषक दुघर्टना बीमा, परिवहन, भूतत्व एवं खनिकर्म, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन आदि विभागो की बिन्दुवार समीक्षा की गई।

मण्डलायुक्त द्वारा मण्डल के तीनो जनपदों में प्रचलित चकबन्दी प्रक्रिया के प्रगति की जानकारी लेते हुए धारा-4, धारा-20, धारा-9, धारा-52 निगरानी एवं अपील आदि के प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। चकबन्दी वादो के निस्तारण के दौरान मण्डलायुक्त ने सभी चकबन्दी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद मीरजापुर के सभी चकबन्दी अधिकारी सितम्बर माह के अन्त तक तीन से पांच वर्ष के मुकदमो का शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में अपर आयुक्त डॉ विश्राम, अपर जिलाधिकारी भू0/रा0/उप निदेशक चकबन्दी देवेन्द्र प्रताप सिंह के अलावा तीनों जनपदो के बन्दोबस्त अधिकारी व चकबन्दी अधिकारी उपस्थित रहें।

जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाएं होंगी स्मार्ट और विकसित, मुख्यमंत्री योगी ने दी कार्ययोजना लागू करने की हरी झंडी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर नगर विकास विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिका के रूप में रूपांतरित करने की योजना पर अमल शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य नगर पालिकाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक-केन्द्रित स्वरूप में विकसित करना है। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत नगर पालिकाओं में गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम और आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन क्रेमेटोरियम और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उत्सव भवन, सामुदायिक केंद्र और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' आधारित ढांचे भी स्थापित किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस योजना को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर लागू किया जा सकता है। इसके तहत लखनऊ और गोरखपुर के एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से समीपवर्ती जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को जोड़ा जाएगा। इससे सुरक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं में आधुनिकता आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।उन्होंने कहा कि प्रत्येक नगर पालिका में परियोजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए तथा वित्तीय संसाधनों का आवंटन नगर निकायों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुरूप किया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि नगर निकायों को उनकी जनसंख्या और कार्यदक्षता के आधार पर 4 से 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित स्वरूप देने से न केवल आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी सेवाएं भी मिलेंगी।

बैठक में लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर संचालित करने तथा अन्य नगरों में 650 बसों की प्रत्यक्ष खरीद का प्रस्ताव भी रखा गया। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।उन्होंने सभी नगर निगमों में निवासियों के कर बकाये से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए अभियान चलाकर आपत्तियां आमंत्रित करने और समाधान शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगर निकायों के पास अपना भवन होना चाहिए।बैठक में नगर निकायों की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि बीते लगभग 20 वर्षों से इन सीमाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप नगर निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने नगर आयुक्त, महापौर, कार्यकारिणी समिति और नगर निगम बोर्ड की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं का तत्काल विस्तार करने का निर्देश दिया।मुख्यमंत्री ने लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज और बहुउद्देशीय खेल परिसर की स्थापना के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को पीपीपी मोड पर प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाए ताकि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ें।

युवतीं ने दर्ज कराया छेड़छाड़ का मुकदमा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने गांव के ही रहने वाले लड़के पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है।

सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के अनुसार वह 19 अगस्त को नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी।जहां से वापस आते समय उसी के गांव के रहने वाले कुलदीप पाल ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ गली गलौज करते हुए छेड़छाड़ करने लगा।पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपित उसे जान से मारने की धमकी देने लगा।पीड़िता किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंची और पूरी घटना अपने भाई को बताई जिसपर उसका भाई जब आरोपित के घर शिकायत करने पहुंचा तो आरोपित पीड़िता के भाई को भी मारने लगा।तब उसने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी।इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की लिखित शिकायत सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस से की है।जिसपर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

ग्रामीण पर्यटन की असली झलक दिखाने निकली फैम ट्रिप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव-2025 के सफल समापन के बाद आज प्रतिभागियों को गांव की असली खुशबू और परंपराओं से जोड़ने के लिए विशेष फैमिलियराइजेशन ट्रिप (फैम ट्रिप) का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य प्रतिभागियों को ग्रामीण जीवन, परंपरागत व्यंजन, लोककला, संस्कृति और स्वयं सहायता समूहों के कार्यों से सीधे परिचित कराना रहा।ट्रिप के दौरान मेहमानों ने खेतों की पगडंडियों पर चलते हुए ग्रामीण परिवेश का अनुभव लिया और स्थानीय समुदाय की जीवनशैली को करीब से देखा। प्रतिभागियों में पीलीभीत, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रूखाबाद, कानपुर, मथुरा, झांसी, जालौन, आगरा और लखीमपुर खीरी सहित विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि शामिल रहे।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि गांव केवल भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की जीवंत धरोहर और असली पहचान हैं। ग्रामीण पर्यटन आने वाले समय में भारत की सॉफ्ट पावर साबित होगा और रोजगार व आत्मनिर्भरता का नया मार्ग दिखाएगा।इकिगाई फार्म स्टे के मालिक कर्नल सहाई ने जोर दिया कि ग्रामीण पर्यटन की सबसे बड़ी ताकत स्थानीय समुदाय की भागीदारी है। वहीं पद्मश्री किसान राम सरन वर्मा ने कहा कि मल्टी-लेयर खेती और फसल विविधीकरण से किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण पर्यटन के नए अवसर खुलते हैं।विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया ने कहा कि पर्यटन अब केवल दर्शनीय स्थलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आत्मा की तलाश का माध्यम बन चुका है। हर घर और हर कला में पर्यटन इकाई बनने की क्षमता है।

छात्रवृत्ति हड़पने वाले मदरसे के तत्कालीन प्रबंधक और प्रधानाचार्य गिरफ्तार, 62 मदरसों से हड़पी 38 लाख

लखनऊ। यूपी के हाथरस में 38 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का गबन करने वाले मदरसे के तत्कालीन प्रबंधक और प्रधानाचार्य को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा की टीम ने शुक्रवार को सिंकदराराऊ से गिरफ्तार कर लिया है। टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि वर्ष 2011 से 2013 के बीच हाथरस के 62 मदरसों में कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 24.92 करोड़ रुपये का घोटाला अंजाम दिया था। अर्जुनपुर के मोतीराय स्थित मदरसा अब्दुल हमीद इस्लामिया एजुकेशन की तत्कालीन प्रबंधक सुधा शर्मा और प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद जांच में दोषी मिले थे। मामले में शासन के निर्देश पर हुई जांच के बाद हाथरस के मुरसान थाने में वर्ष 2014 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी जांच बाद में ईओडब्ल्यू के सुपुर्द कर दी गई थी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिल रही गति, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे सख्त मॉनिटरिंग

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण के कार्य तेजी से संचालित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में ग्रामीण इलाकों को मजबूत रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माणाधीन सड़कों का नियमित निरीक्षण किया जाए और कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यूपीआरआरडीए) के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत 2,565 मार्गों को स्वीकृति मिली है, जिनकी कुल लंबाई 18,938.04 किलोमीटर है। इन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14,638.72 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है। इनमें एफडीआर तकनीक से बनने वाले 747 मार्ग शामिल हैं, जिनकी लंबाई 5,820.796 किलोमीटर और स्वीकृत लागत 5,992.71 करोड़ रुपये है। एफडीआर तकनीक वाले मार्गों में से 5,000 किलोमीटर लंबे मार्गों का सरफेसिंग सहित निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि कुल 5,220 किलोमीटर का एफडीआर कार्य संपन्न हो चुका है।

पूर्व निर्मित सड़कों पर पीरियॉडिक रिन्यूवल का कार्य भी योजना का अहम हिस्सा है। इसके लिए भारत सरकार से प्राप्त इंसेंटिव मनी की धनराशि से प्रदेश के 62 जनपदों में 306 मार्गों पर कार्य स्वीकृत हुआ है। इनकी कुल लंबाई 1,911.304 किलोमीटर है और लागत 494.02 करोड़ रुपये तय की गई है।

यह कार्य कोल्ड मिक्स, वेस्ट प्लास्टिक, सीजीबीएम और एमएसएस+ तकनीक से 30 मिमी बीसी परत बिछाकर किया जा रहा है। वर्तमान में इन मार्गों का अनुबंध संपन्न कर निर्माण प्रगति पर है। यूपीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि अब तक वेस्ट प्लास्टिक के उपयोग से 630 किलोमीटर लंबे मार्गों का रिन्यूवल कार्य पूरा किया जा चुका है। इसमें 710 टन प्लास्टिक का पुनः उपयोग किया गया है। इस तकनीक से न केवल सड़कों की मजबूती बढ़ी है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का भी बेहतर समाधान मिल रहा है।

संक्षेप

लोहे के खंभे में करंट उतरने से दहशत

लखनऊ। गोसाईगंज क्षेत्र के मोअज्जम नगर में बिजली की लाइन के पास लगे लोहे के खम्भे में बिजली का करेंट आने से लोग दहशत मे है। गोसाईगंज क्षेत्र में स्थित मोअज्जम नगर गांव में बिजली की लाइन के पास ही एक लोहे का खम्भा लगा हुआ है।उस लोहे के खम्भे में बिजली के तार टच होने पर उसमें करेंट आ जाता है जिससे वहां के लोग काफी दहशत में हैं।हालांकि ग्रामीणों ने कस्टमर केयर के टोलफ्री नम्बर पर इसकी शिकायत भी की है जिसका कम्प्लेंट रजिस्ट्रेशन नम्बर एमवी21082505504 दिया गया है लेकिन समस्या का निस्तारण अभी तक नही किया जा सका है।

पितृपक्ष में गया के लिए विशेष बस सेवा शुरू, पिंडदान व तर्पण के लिए जाने वालों को मिलेगी सुविधा

लखनऊ। परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान एवं तर्पण के लिए तमाम लोग बिहार के गया जाते हैं। इनके लिए बस सेवा शुरू की गई है। बस वाराणसी के सारनाथ से बोधगया बिहार जाएगी। वाराणसी (कैंट) से संचालित बस चंदौली-सासाराम-औरंगाबाद-शेरघाटी-गया (बिहार) तक चलेगी। वाराणसी स्टेशन से रात आठ बजे चलकर यह बस गया (विहार) भोर में चार बजे पहुंचेगी। बस का किराया वाराणसी से बिहार तक 465 रुपये है। इसी प्रकार लखनऊ (आलमबाग बस टर्मिनल) से मुजफ्फरपुर का किराया 862 रुपये है। यह बस सेवा लखनऊ से रात दो बजे चलकर बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर, तुमकुही, गोपालगंज होते हुए अगले दिन सुबह चार बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।

लखनऊ के राजकीय आईटीआई में प्रवेश का अंतिम अवसर, 24 अगस्त तक करें आवेदन

लखनऊ। जनपद के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सत्र 2025 के चतुर्थ चरण में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं।यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए भी उपलब्ध है जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले सके अथवा चयन सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को अपना प्रार्थना पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र, रैंक पत्र, आधार कार्ड तथा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र लेकर जनपद के किसी भी राजकीय आईटीआई में उपस्थित होना होगा।सूचना के अनुसार चतुर्थ चरण की मेरिट सूची 25 अगस्त 2025 को जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल अभिलेखों और उनकी छायाप्रतियों के साथ 26 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक संबंधित संस्थान में प्रवेश लेना होगा।

पत्रकारों व आश्रितों के लिए दो दिवसीय शिविर सम्पन्न, 400 ने कराया डेटा संशोधन व ई-केवाईसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों (राज्य एवं जनपद स्तरीय) एवं उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सुगमता से चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मुख्यालय लखनऊ के सभागार में 21 एवं 22 अगस्त को दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का संचालन स्टेट हेल्थ एजेंसी (सांचीज़) की सीईओ अर्चना वर्मा के नेतृत्व में टीम द्वारा किया गया।अपर निदेशक सूचना अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि शिविर में लगभग 400 पत्रकारों ने बीआईएस (लाभार्थी पहचान प्रणाली) डेटाबेस में उपलब्ध डाटा में अपने एवं आश्रितों का संशोधन और ई-केवाईसी करवाया। उन्होंने कहा कि अब मान्यता प्राप्त पत्रकार आधार कार्ड के अनुरूप अपडेटेड सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नया आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा लेने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी।उन्होंने यह भी अवगत कराया कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध होगा।इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त समिति के प्रतिनिधि, सूचना विभाग के प्रेस प्रभाग से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

भारतीय इतिहास और कला में राम की झलकः डॉ. संजीव कुमार सिंह के व्याख्यान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व विभाग द्वारा आयोजित पुरातत्त्व अभिरुचि पाठ्यक्रम के तृतीय दिवस पर आज दो विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए। दोनों सत्रों में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, अयोध्या के निदेशक एवं प्रबंधन सलाहकार डॉ. संजीव कुमार सिंह ने क्रमशः "भारतीय इतिहास में राम" और "रामानुभूति भारतीय कला में राम" विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।अपने पहले व्याख्यान में डॉ. सिंह ने श्रीराम की ऐतिहासिकता को स्पष्ट करते हुए उनके जीवन से जुड़े विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय मेसंकलित पुरातात्त्विक प्रमाणों को दर्शाते हुए राम को अवतारी पुरुष सिद्ध किया।दूसरे सत्र में उन्होंने भारतीय कला में राम के स्वरूप और चरित्र को प्रस्तुत करते हुए बताया कि रामानुभूति केवल भक्ति या कर्मकांड तक सीमित न होकर एक तात्त्विक और भावनात्मक श्रेणी है, जो श्रीराम को आध्यात्मिक और अस्तित्वगत स्तर पर जोड़ती है। उन्होंने उल्लेख किया कि पुरातत्त्वविद् बी.बी. लाल ने सर्वप्रथम साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर रामायण में वर्णित स्थलों की प्रमाणिकता खोजकर राम की ऐतिहासिकता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया।डॉ. सिंह ने कहा कि इतिहास में राम हमें आदर्श जीवन का मार्ग दिखाते हैं, जबकि कला में राम हमारे भाव-जगत को आलोकित करते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में राम आज भी जीवंत हैं और सदैव रहेंगे।कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व विभाग की निदेशक रेनू द्विवेदी ने स्मृति-चिन्ह और पौधा भेंट कर डॉ. सिंह का अभिनंदन किया तथा सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रकाशन सहायक बलिहारी सेठ ने किया।इस अवसर पर विभाग के उत्खनन एवं अन्वेषण अधिकारी राम विनय, अभयराज सिंह, संतोष कुमार सिंह, अकील खान, आशीष कुमार, विभा, हिमांशु, मयंक सहित अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्राविधिक शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठकें, चार नए इंजीनियरिंग कॉलेजों का संचालन शुरू

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें सम्पन्न हुईं। पहली बैठक गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में स्थापित चार नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रगति और संचालन की स्थिति पर केंद्रित रही, जबकि दूसरी बैठक में प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में प्राविधिक शिक्षा की भूमिका पर चर्चा की गई।बैठक में अवगत कराया गया कि चारों इंजीनियरिंग कॉलेज 1 अगस्त 2025 से अपने-अपने परिसरों में संचालित हो रहे हैं। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का पंजीकरण जारी है और उनकी इंडक्शन क्लास प्रारंभ हो चुकी हैं। द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। कॉलेजों के शैक्षिक भवन, कक्ष और प्रयोगशालाएं तैयार हैं। प्रथम व द्वितीय वर्ष की प्रयोगशालाओं के उपकरण प्राप्त हो चुके हैं।मंत्री ने निर्देश दिया कि वेतन और गैर वेतन मद में 31 मार्च 2026 तक के संभावित व्यय का पूर्वानुमान तैयार कर विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत की जाए। साथ ही गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने जिले के पुलिस अधीक्षक और कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कॉलेज परिसरों का निरीक्षण करें। सुरक्षा व्यवस्था, निर्माण गुणवत्ता और प्रबंधन की समीक्षा कर किसी भी कमी का तत्काल निराकरण कराने को कहा गया। चारों कॉलेजों में ऑडिटोरियम निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ए.के.टी.यू. लखनऊ के कुलपति को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।इसी दिन आयोजित दूसरी समीक्षा बैठक में मंत्री ने प्राविधिक शिक्षा की भूमिका को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य से जोड़ा। इसमें प्लेसमेंट पोर्टल विकास, निजी क्षेत्र से सहयोग और NBA एक्रिडिटेशन जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा हुई। ए.के.टी.यू. लखनऊ द्वारा तैयार प्लेसमेंट पोर्टल को अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया।बैठक में यह भी तय किया गया कि ए.के.टी.यू. लखनऊ और उससे संबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की अंग्रेजी दक्षता और संवाद क्षमता बढ़ाने के लिए पांच दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कुलपति को अपर मुख्य सचिव के साथ विचार-विमर्श कर शीघ्र निर्णय लेने और जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

व्यापार मंडल ने जीएसटी दरों में संशोधन की मांग उठाई

लखनऊ। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने आज कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले 'एक देश, एक टैक्स' की अवधारणा सामने रखी गई थी, लेकिन व्यवहार में अभी भी वस्तुओं पर अलग-अलग दरें लागू हैं। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में जीएसटी की 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत दरें समाप्त कर 5 और 18 प्रतिशत रखने की बात कही गई है, इस पर व्यापारियों का मत है कि 18 और 28 प्रतिशत दरों को पूरी तरह खत्म कर सभी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर केवल 5 प्रतिशत कर होना चाहिए।उन्होंने कहा कि कर की दरें जितनी अधिक होती हैं, टैक्स चोरी की संभावना उतनी ही बढ़ती है। वर्तमान स्थिति में एक ही वस्तु वर्ग में तीन-तीन प्रकार की कर दरें लागू हैं, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को असुविधा होती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रेडीमेड वस्त्रों पर 999 रुपये तक 5 प्रतिशत और उससे ऊपर 12 प्रतिशत टैक्स है।

छात्रवृत्ति हड़पने वाले मदरसे के तत्कालीन प्रबंधक और प्रधानाचार्य गिरफ्तार, 62 मदरसों से हड़पी 38 लाख

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। यूपी के हाथरस में 38 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का गबन करने वाले मदरसे के तत्कालीन प्रबंधक और प्रधानाचार्य को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा की टीम ने शुक्रवार को सिंकदराराऊ से गिरफ्तार कर लिया है। टीम आगे की कार्रवाई कर रही है।

बता दें कि वर्ष 2011 से 2013 के बीच हाथरस के 62 मदरसों में कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 24.92 करोड़ रुपये के घोटाले को अंजाम दिया गया था। अर्जुनपुर के मोतीराय स्थित मदरसा अब्दुल हमीद इस्लामिया एजुकेशन की तत्कालीन प्रबंधक सुधा शर्मा और प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद जांच में दोषी मिले थे।

मामले में शासन के निर्देश पर हुई जांच के बाद हाथरस के मुरसान थाने में वर्ष 2014 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी जांच बाद में ईओडब्ल्यू के सुपुर्द कर दी गई थी। ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद 81 आरोपियों (3 लोक सेवक एवं 78 निजी व्यक्ति) को गबन का दोषी पाया था।

इसमें से 46 के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। शेष 32 आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। डीजी ईओडब्ल्यू के निर्देश पर शुक्रवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा।

वहीं दूसरी ओर डीजी ईओडब्ल्यू नीरा रावत ने लखनऊ सेक्टर को जुलाई माह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर शुक्रवार को सम्मानित किया। वहीं निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा को सर्वश्रेष्ठ विवेचक का पुरस्कार दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में असीम अरुण ने दिए पारदर्शिता और नवाचार पर जोर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण लगातार विभाग की योजनाओं में पारदर्शिता, निगरानी और नवीनीकरण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को उन्होंने गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक और सभी योजनाधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से योजनाओं में सुधार और आवश्यक बदलावों के सुझाव रखे।राज्यमंत्री ने योजनाओं के पुनः नवीनीकरण, नियमावलियों के प्रख्यापन, परिचलन तथा पुराने शासनादेशों को समाप्त कर नए आदेश जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि समय-समय पर एसओपी की समीक्षा और संशोधन किया जाए, पुराने सॉफ्टवेयर को अद्यतन किया जाए और आवश्यकतानुसार नए सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएं। साथ ही सर्वोदय विद्यालयों की प्रशासनिक और शैक्षिक व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाकर उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाए।बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए तहसील स्तर पर सुलह अधिकारी नियुक्त करने, वृद्धाश्रमों के संचालन व निगरानी के लिए नियामक इकाई गठित करने, डे-केयर संचालन और वरिष्ठ नागरिक बोर्ड को सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा जातिवाद आधारित छात्रावास संचालन को समाप्त कर समरसता की दिशा में कदम बढ़ाने, छात्रावास भवन का नया प्रारूप तैयार करने और शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

दक्षिणी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, गरज-चमक के साथ वज्रपात की भी आशंका

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। त्तर प्रदेश में मानसून के दोबारा सक्रिय होने से मौसम ने करवट लिया है। मौसम विभाग ने 22 से 25 अगस्त के बीच प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रुक-रुककर कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है।

शुक्रवार को दक्षिणी, पूर्वी और तराई इलाके में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिली। पूर्वी यूपी के जौनपुर में सर्वाधिक 80 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं लखीमपुर खीरी और महराजगंज में 70 मिमी बारिश दर्ज की गई।

24 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार के लिए प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, आगरा समेत प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 59 जिलों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम के असर से यूपी के ज्यादातर इलाकों में 22 से 25 अगस्त के बीच चार दिन अच्छी बारिश के आसार हैं। 24 व 25 अगस्त को बारिश के और जोर पकड़ने के संकेत हैं।

इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है।

इन जिलों में गरज-चमक से साथ वज्रपात की आशंका

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर आदि में गरज-चमक से साथ वज्रपात की आशंका है।

उपराष्ट्रपति पद पर सीपी राधाकृष्णन का चुना जाना लगभग तय

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अब सरकार और विपक्ष के प्रत्याशियों के मध्य मुकाबला होना तय हो गया है। सरकार द्वारा सीपी राधाकृष्णनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इंडी ब्लाक ने भी सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस बार उपराष्ट्रपति के पद के दोनों ही प्रत्याशी एक ही प्रान्त तमिलनाडु से आते हैं। कांग्रेस व विरोधी दलों को लगा कि अगर एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन देश के नये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी राधाकृष्णन के माध्यम से दक्षिण विशेषकर तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जमीन को सशक्त करने का प्रयास करेगी क्योंकि जब बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना प्रत्याशी बनाया था तब भाजपा को राजस्थान में राजनैतिक लाभ हुआ था और वहां उसकी सत्ता में वापसी हो गई थी। अब भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को अपना प्रत्याशी बनाकर तमिलनाडु की जनता व कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया है।

कौन है सीपी राधाकृष्णन- संसद के दोनों सदनों के वर्तमान अंकगणित के अनुसार एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का विजयी होना सुनिश्चित है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तथा दो बार कोयंबटूर से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही 1974 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर समाज सेवा के कार्यों में लग गए और बाद में उनके राजनैतिक जीवन का आरम्भ हुआ। सीपी राधाकृष्णन कुछ समय तक झारखंड के भी राज्यपाल रहे, वह झारखण्ड राज्य के सभी जिलों का दौरा करने वाले राज्यपाल हैं। सीपी राधकृष्णन तेलंगना के राज्यपाल व पुडडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल चुके हैं। सी पी राधाकृष्णन तमिलनाडु की राजनीति में 40 वर्ष तक सक्रिय रहे जिसका प्रतिफल अब उन्हें उपराष्ट्रपति पद के रूप में मिलने जा रहा है।

वह 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव नियुक्त हुए। 2004 में संयुक्तराष्ट्र महासभा में संसदीय प्रतिनिधमंडल के हिस्से के रूप में भाषण दिया और ताइवान की पहली संसदीय यात्रा में शामिल हुए। वह 2020 से 2022 तक केरल बीजेपी प्रभारी भी रहे। सीपी राधाकृष्णन एक बहुत अनुभवी तथा जमीनी कार्यकर्ता हैं जिन्हें इतना बड़ा उत्तरदायित्व प्राप्त हो रहा है।

सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद को मिटाने, समान नागरिक संहिता लागू करने, छुआछूत समाप्त करने और नषे के खतरे से निपटने जैसी मांगो को लेकर 93 दिनों में 19 हजार किमी लंबी रथयात्रा निकाली थी। माना जा रहा है कि भाजपा ने इस बार वैचारिक पृष्ठभूमि के नेता को प्राथमिकता दी है जिसका लाभ उसे दक्षिण की आगामी राजनीति में मिल सकता है।

चुनावी राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन के ओबीसी समाज से होने का लाभ भी बीजेपी को दक्षिण राज्यों के चुनावों में मिल सकता है। भाजपा अब कांग्रेस तथा विपक्ष के खिलाफ इस बात का माहौल भी बनाने का प्रयास करेगी कि विपक्ष ने ओबीसी समाज के प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति बनने से रोकने का प्रयास किया यद्यपि बीजेपी प्रत्याशी का जीतना तय है क्योकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 392 वोट चाहिए जबकि एनडीए के पास 422 वोट हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी चयन करते समय भी कांग्रेस व विपक्ष की दोहरी मानसिकता बेनकाब हो गई है क्योकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रामजन्मभूमि मंदिर का फैसला सुनाने वाले एक जज को राज्यसभा में भेजा था और एक को राज्यपाल बनाया था तब विपक्ष ने रिटायर्ड हो चुके जजों की नियुक्तियों का विरोध किया था और अब स्वयं ही एक रिटायर्ड जज को प्रत्याशी बना रही है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसदीय प्रणाली का औसत प्रदर्शन शर्म वाली बात है

दोनों सदनों में कामकाज की स्थिति वाकई काफी चिंताजनक रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार, 419 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे, किंतु बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण मात्र 55 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर हो पाए।

नीरज कुमार दुबे

भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच संसद जनता के प्रतिनिधियों को नीति और विधायी कार्यों पर गहन विमर्श का अवसर प्रदान करता है। लेकिन आज संपन्न मानसून सत्र इसका विपरीत चित्र प्रस्तुत करता है। हम आपको बता दें कि लगभग एक महीने तक चले इस सत्र में लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 15 विधेयक पारित किए। कागज़ों पर यह भले उपलब्धि दिखती है, किंतु वास्तविकता यह है कि अधिकांश विधेयक बिना सार्थक चर्चा के शोर-शराबे और हंगामे के बीच पारित हुए।

दोनों सदनों में कामकाज की स्थिति वाकई काफी चिंताजनक रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार, 419 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे, किंतु बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण मात्र 55 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर हो पाए। साथ ही जहां सत्र की शुरुआत में 120 घंटे चर्चा का लक्ष्य रखा गया था, वहीं विपक्ष के निरंतर गतिरोध के चलते सदन केवल 37 घंटे ही चर्चा कर सका। इसी तरह राज्यसभा का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। उपसभापति हरिवंश के अनुसार, सदन का कुल कामकाज मात्र 38.88 प्रतिशत ही हुआ और शून्यकाल तथा प्रश्नकाल एक बार भी सामान्य तरीके से संचालित नहीं हो सका। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि संसदीय प्रणाली अपनी गुणवत्ता और प्रभावशीलता खोती जा रही है।

हम आपको याद दिला दें कि सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर की थी कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। बावजूद इसके, विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मुद्दों पर हंगामा करते हुए लगातार कार्यवाही ठप रखी। परिणामस्वरूप कई सांसद, जो अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को उठाने की तैयारी के साथ संसद पहुँचे थे, अपनी बात रखने से वंचित रह गए। यह न केवल सांसदों की भूमिका को कमतर करता है बल्कि जनता की आकांक्षाओं को भी ठेस पहुँचाता है।

देखा जाये तो संसद का मूल उद्देश्य है—कानून निर्माण पर व्यापक चर्चा और विमर्श। चर्चा से कानून के पक्ष-विपक्ष, उसके प्रभाव और संभावित खामियों पर प्रकाश पड़ता है। किंतु हंगामे के बीच जब विधेयक संक्षिप्त औपचारिकता के बाद पारित होते हैं, तो उनकी गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों प्रभावित होती हैं। यह न केवल विधायी प्रक्रिया की गंभीरता को कम करता है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को भी आहत करता है।

इसके अलावा, जिस तरह अन्य क्षेत्रों में नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू है, उसी तरह सांसदों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए। यदि वह जानबूझकर हंगामे और व्यवधान के कारण संसद का काम ठप करते हैं, तो करदाताओं के पैसों से मिलने वाले वेतन और भत्तों पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता। साथ ही, जिस तरह दागी नेताओं को एक माह तक जेल में रहने पर स्वतः उनका मंत्री पद समाप्त होने के प्रावधान वाला विधेयक पेश किया गया है उसी तरह लगातार हंगामा करने वाले सांसदों की सदस्यता स्वतः समाप्त करने पर भी गंभीर विचार होना चाहिए। यह लोकतंत्र को बचाने और संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

इसके अलावा, यह भी दिलचस्प रहा कि सत्र से पहले यह अपेक्षा थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के पद से हटाने की प्रक्रिया प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेगी। किंतु अप्रत्याशित रूप से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने इस मानसून सत्र को एक ऐतिहासिक राजनीतिक मोड़ दे दिया।

इसके अलावा, भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और पूरा राष्ट्र इस लक्ष्य की दिशा में गति पकड़ चुका है। लेकिन जब संसद में विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर व्यवधान डालते हैं, तो यह सीधे-सीधे विकसित भारत की राह में रोड़ा डालने जैसा है। देखा जाये तो विकास की गति केवल सड़कों, पुलों और उद्योगों से नहीं तय होती, बल्कि सुचारु और प्रभावी विधायी व्यवस्था से भी होती है। संसद ही वह स्थान है जहां नीतियों का खाका तैयार होता है, संसाधनों का प्रबंधन तय होता है और जनता की आवाज़ नीतियों में रूपांतरित होती है। यदि यही मंच बार-बार शोर-शराबे में जकड़ जाए और कार्यवाही बाधित हो, तो विकास की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी?

विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार को कटघरे में खड़ा करे, सवाल पूछे और जनहित के मुद्दों पर रचनात्मक बहस करे। लेकिन विपक्ष यदि सवाल पूछने की बजाय हंगामा करने को ही हथियार बनाए, तो यह लोकतंत्र के साथ ही देश की विकास यात्रा के साथ अन्याय है। संसद का हर मिनट करदाताओं के करोड़ों रुपये के बराबर होता है। ऐसे में यह समय और धन व्यर्थ करना देश की प्रगति में बाधा डालने जैसा है। आज जब पूरा भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तब विपक्षी सांसदों को चाहिए कि वह हंगामा छोड़कर सार्थक बहस और ठोस सुझावों के माध्यम से योगदान करें। विकास केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र और समाज का साझा दायित्व है। यदि संसद ही ठप कर दी जाएगी, तो विकसित भारत का संकल्प केवल एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा।

बहरहाल, स्पष्ट है कि भारतीय संसदीय प्रणाली इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। आंकड़े बताते हैं कि संसद का अधिकांश समय सार्थक चर्चा और विधायी कार्यों की बजाय शोर-शराबे में नष्ट हो रहा है। विपक्ष यदि लोकतंत्र की रक्षा का दावा करता है, तो उसे पहले संसद की कार्यप्रणाली को ठप करने की बजाय संवाद और बहस के रास्ते पर लौटना होगा। लोकतंत्र बहुमत और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी से चलता है। संसद को हंगामे की भेंट चढ़ाना देश और जनता के हितों को सीधा नुकसान पहुँचाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि संसद में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियम बनाए जाएं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं लेकिन यदि हमारी संसदीय प्रणाली औसत दर्जे का प्रदर्शन

अजब-गजब

गर्लफ्रेंड ने प्यार नहीं प्रेमी का किया सौदा, नर्क में युवक को धकेलकर कमाए 11 लाख

प्यार में इंसान एकदूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई भी धोखा ना दे! हालांकि कई बार प्यार को लेकर हैरान करने वाले किस्से लोगों के बीच सामने आते रहते हैं। जिन्हें देखने के बाद लोगों को काफी ज्यादा हैरानी होती है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों चीन से सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की रहने वाली एक 17 साल की लड़की को 19 साल के लड़के से प्यार हुआ और इस प्यार का लड़की ने बाद में जाकर सौदा कर दिया। जिसके बदले उसे 11 लाख रुपये मिले।

डेली स्टार में आई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के झानजियांग निवासी, 19 साल के एक लड़के को एक 17 साल की गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया और उसे एक म्यांमार के एक ऑनलाइन स्कैमर गैंग के पास बेच दिया। इस पूरे किस्से को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके हनीट्रैप जैसा कुछ है। जहां उसे फैमली बिजनेस के नाम पर लड़की बहला-फुसलाकर उसे ले गई और उसे साइबर स्कैमर गिरोह के हाथों बेच दिया।

म्यांमार के साइबर क्राइम गिरोह ने लड़के को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। जिस कारण उसका वजन दर्जनों पाउंड कम हो गया और उसकी सुनने की शक्ति भी लगभग खत्म हो गई। इसके बारे में जब परिवार के लोगों को पता चला तो उसे बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई गई और भारी फिरौती देने के बाद उसे अपने देश वापस लाया जा सका। परिवार वालों के अनुसार, स्कैमर उससे लोगों से पैसा ठगने के लिए कहते थे और उससे 20-20 घंटे काम करवाया जाता था।

लड़की की बहन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे भाई पर वहां काफी ज्यादा अत्याचार हुए है। उसे अंधेरे कमरे में ले जाकर लोहे की छड़ों से कानों और कूल्हों पर मारा जाता था। जब हमें लोगों को इस बात की खबर लगी तो हमने स्कैमर से संपर्क किया और उन्हें 350,000 युआन (42,54,190।50 रुपये) का भुगतान किया। जिसके बाद मेरा भाई घर वापस आ सका। हालांकि युवक की प्रेमिका को दस बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

ब्लॉग

विधेयक पर हंगामा क्यों, जब मुद्दा है राजनीतिक शुचिता का

ललित गर्ग

गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे नेता चाहे वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री ही क्यों न हो, उनकी गिरफ्तारी या हिरासत के बाद एक निश्चित अवधि बीत जाने पर हटाने की व्यवस्था वाले विधेयक को जब केन्द्र सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत किया तो जरूरत से ज्यादा हंगामा एवं विरोध समझ में नहीं आया। इस तरह ईमानदार, अपराधमुक्त राजनीति एवं चरित्रसम्पन्न-पवित्र राजनेताओं की पैरवी वाले विधेयक पर हंगामा लोकतंत्र की गरिमा को आहत करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी ओर से इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया, अब तो विपक्ष को विरोध एवं हंगामें को विराम देते हुए इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी ईमानदार, समानतापूर्ण एवं आदर्श व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए, जिससे उच्च पदों पर बैठे नेताओं के गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिये जाने पर उनके लिये पद छोड़ना आवश्यक हो जाये? आखिर इस आदर्श व्यवस्था में समस्या क्या है? क्यों विपक्ष नैतिक एवं आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में अवरोधक बनकर अपने नैतिक चरित्र पर प्रश्न खड़े कर रहा है? क्या इस विधेयक का असर सत्तापक्ष के नेताओं पर नहीं होगा?

आजादी के बाद से कतितय राजनीतिक विसंगतियों के चलते राजनीति में अपराधी तत्वों का वर्चस्व बना रहा है। जनता यह अपेक्षा करती है कि जिन्हें वह अपना प्रतिनिधि चुनती है, वे अपराधमुक्त, निष्कलंक, ईमानदार और चरित्रवान हों। परन्तु स्थिति इसके विपरीत दिखती रही है। एक ओर जनप्रतिनिधि अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, दूसरी ओर वे पद से इस्तीफा देने या सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बजाय सत्ता की कुर्सी से चिपके रहते हैं। यही प्रवृत्ति जनता के विश्वास को तोड़ती है और राजनीति को संदेह के घेरे में डाल देती है। यह प्रश्न अब और गंभीर हो उठा है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को शासन और सत्ता के उच्च पदों पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या लोकतंत्र का आधार अपराध और भ्रष्टाचार पर खड़ा किया जा सकता है? निश्चित ही नहीं। जब तक राजनीति से अपराधी तत्वों का निष्कासन नहीं होगा, तब तक न तो सुशासन स्थापित हो सकता है न ही नया भारत, विकसित भारत एवं आदर्श भारत बन सकता है और न ही राजनीति के प्रति जनता का भरोसा लौट सकता है।

आज समय आ गया है कि नए कानून बनाकर राजनीति को अपराधमुक्त बनाने की दिशा में ठोस एवं कारगर कदम उठाए जाएं। यह केवल चुनाव सुधार का मामला नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का प्रश्न है। ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि जिस क्षण कोई जनप्रतिनिधि गंभीर अपराध में आरोपित होकर जेल भेजा जाए या आरोप सिद्ध होने तक हिरासत में रहे, वह स्वचालित रूप से अपने पद से मुक्त हो जाए। इस्तीफे की प्रतीक्षा या राजनीतिक दबाव की आवश्यकता ही न रहे। अनेक नेताओं ने ऐसा आदर्श प्रस्तुत भी किया, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आदि अनेक पार्टियों के नेताओं ने जेल से सरकारें चलाने एवं मंत्री पद पर बने रहने के काले अध्याय रचे हैं, इसी के चलते इस नये विधेयक की अपेक्षा सामने आई।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में स्वच्छ राजनीति केवल आदर्श नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। जब सत्ता और शासन के केंद्र में अपराधी मानसिकता के लोग बैठते हैं, तो वे शासन को अपने स्वार्थ और अपराधों की ढाल बना लेते हैं। इससे न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था खोखली होती है, बल्कि आम जनता का जीवन भी संकट में पड़ता है। भ्रष्टाचार, धनबल, बाहुबल, भाई-भतीजावाद, हिंसा और अनैतिकता का वातावरण उसी समय पनपता है, जब राजनीति अपराधियों के कब्जे में जाती है। ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले नेताओं की मांग आज पहले से अधिक बढ़ गई है। जनता ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करे। राजनीति यदि सेवा और त्याग का माध्यम बनेगी तो ही समाज का कल्याण होगा। जिन नेताओं पर जरा भी संदेह का धुंधलका हो, उन्हें स्वयं स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए। यही परंपरा राजनीति को उच्चता और गरिमा प्रदान कर सकती है।

अपराधमुक्त राजनीति केवल नैतिक अपेक्षा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूरी है। जब तक राजनीति में शुचिता और नैतिकता का स्थान नहीं बनेगा, तब तक सुशासन और ईमानदार प्रशासन की कल्पना अधूरी ही रहेगी। नए कानूनों का निर्माण कर अपराधियों के लिए राजनीति के दरवाजे बंद करना समय की सबसे बड़ी मांग है। यह कदम न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा, बल्कि जनता के भीतर यह विश्वास भी जगाएगा कि राजनीति वास्तव में लोककल्याण के लिए है, न कि अपराधियों की शरणस्थली। यही अपराधमुक्त राजनीति का दर्शन है, जहां सत्ता अपराधियों का आश्रय-स्थल न होकर समाज की नैतिक ऊर्जा का केंद्र बने। यही उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कि वह लोकतंत्र को उसकी वास्तविक आत्मा लौटाए और राजनीति को सेवा, शुचिता और ईमानदारी का प्रतीक बनाए।

भारतीय लोकतंत्र में पिछले कुछ वर्षों से राजनीति और अपराध के गठजोड़ को लेकर गहरी चिंता लगातार उठती रही है। जनता बार-बार यह अपेक्षा करती है कि जिन्हें वे संसद और विधानसभा भेजते हैं, वे न केवल ईमानदार और पारदर्शी हों बल्कि उनके चरित्र और आचरण पर कोई दाग न हो। किंतु बार-बार यही देखने को मिलता है कि गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे नेता भी उच्च पदों पर बने रहते हैं और शासन-सत्ता का उपयोग अपने बचाव के लिए करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया नया विधेयक (संविधान का 130वां संशोधन) एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है, केन्द्र सरकार इन विधेयकों को भ्रष्टाचार एवं अपराध विरोध बता रही है, जबकि विपक्ष इससे सहमत नहीं। उनकी असहमति अनेक प्रश्नों को खड़ा कर रही है कि आखिर विपक्ष दागियों की वकालत करते हुए वह स्वयं भी दागी क्यों बन रही है? आशंका जताई जा रही है कि यदि यह संशोधन पारित हो गया तो विपक्ष-शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री अस्थिर हो सकते हैं, उनके पद संकट में पड़ सकते हैं। दरअसल यह विरोध केवल विधेयक का नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक सुविधा, अपनी सत्ता बचाने और सुरक्षा का है। प्रश्न यह उठता है कि क्या विपक्ष वास्तव में अपराधमुक्त राजनीति नहीं चाहता? क्या केवल सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति को अपराधियों का अड्डा बनाए रखना आवश्यक है?

विपक्ष का तर्क है कि सरकार इस विधेयक का दुरुपयोग कर सकती है, और केवल आरोप लगाकर भी नेताओं को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में जब तक कानून कठोर और स्पष्ट नहीं होगा, तब तक राजनीति से अपराध का सफाया संभव नहीं है। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप गलत सिद्ध होता है तो उसके लिए पुनः प्रतिष्ठा अर्जित करने के रास्ते खुले रहेंगे, परंतु गंभीर आरोपियों को शासन की कुर्सी पर बने रहने देना लोकतंत्र के साथ अन्याय है, उसकी मूल आत्मा को ध्वस्त करना है। ऐसा अरविन्द केजरीवाल ने पहली बार किया और जेल से ही सरकार चलाने का दम भरते रहे।

आज देश 'विकसित भारत' के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना केवल तकनीकी प्रगति या आर्थिक मजबूती से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए स्वच्छ, ईमानदार और पारदर्शी राजनीति आवश्यक है। राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ न केवल लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है बल्कि जनता के विश्वास को भी तोड़ती है। अपराधमुक्त राजनीति न केवल आदर्श है बल्कि सुशासन और विकास की बुनियादी शर्त है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे विधेयक का स्वागत किया जाए, क्योंकि यह राजनीति को शुचिता, नैतिकता और जनहित के मार्ग पर ले जाने का प्रयास है। राजनीति में एक नये सूरज का उदय है। विपक्ष यदि इसका विरोध करता है तो यह सवाल स्वतः उठता है कि क्यों विपक्ष अपराधमुक्त राजनीति का विरोध करके अपराधियों का संरक्षण कर रहा है? क्या उसे अपने ही दागी नेताओं के लिए भय है? लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने के लिए यह विधेयक समय की मांग है। नया भारत तभी विकसित भारत बनेगा जब उसकी राजनीति अपराधियों से मुक्ति होगी। अपराधमुक्त राजनीति से ही सुशासन आएगा, ईमानदार नेतृत्व पनपेगा और जनता के बीच विश्वास की नई रोशनी जगेगी। यही लोकतंत्र की असली जीत होगी।

यथास्थिति बनी रहे... सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। उत्तर प्रदेश की संभल मस्जिद मामले में 25 अगस्त तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया है। जस्टिसी पीएसन रसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 मई के आदेश के खिलाफ संभल मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हिन्दु पक्षों की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा था कि संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमा प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के तहत नहीं आएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि चुनौती हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष को लेकर है कि यह मुकदमा प्लेसेस

ऑफ वरशिप एक्ट के तहत नहीं आएगा। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि क्या इस मामले को प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट से संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

हिंदू पक्ष ने क्या दिया तर्क?

हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित मुद्दा ही नहीं उठता। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि संभल मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित एक स्मारक है, इसलिए यह अधिनियम के दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि वादी केवल स्मारक तक पहुंच की मांग कर रहे हैं।

जैन ने आगे दलील दी कि कोर्ट की एक अन्य पीठ ने आज एक आदेश पारित किया है कि एएसआई की ओर से संरक्षित एक स्मारक प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट नहीं आता। इसके बाद पीठ ने जैन को सोमवार को इस आदेश पेश करने को कहा। जस्टिस नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित करते हुए कहा कि हम उस आदेश को देखेंगे। हम असंगत आदेश पारित नहीं करना चाहते। तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है।

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी मस्जिद समिति की याचिका

हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें मस्जिद परिसर की स्थानीय जांच के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया था। पिछले साल नवंबर में आयुक्त के मस्जिद दौरे के कारण इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में निचली अदालत की कार्यवाही पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि हाई कोर्ट मस्जिद समिति की चुनौती पर फैसला नहीं सुना देता।

मणि महेश कैलाश यात्रा से वापसी पर श्रद्धालुओं का हुआ स्वागत

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में शामिल व कठिन यात्राओं में से एक हिमाचल प्रदेश के बुद्धिल घाटी में भरमौर से 21 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13385 फीट ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश कैलाश यात्रा श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से एक बड़ी आस्था की यात्रा रही है, मान्यता है कि भगवान शिव मणिमहेश के कैलाश शिखर पर निवास करते हैं जो मणिमहेश झील से दिखाई देता है। यह यात्रा नवीं शताब्दी में स्थानीय राजा राजा साहिल बर्मन द्वारा भगवान शिव का दर्शन प्राप्त होने के बाद शुरू हुई थी और उन्होंने ही मणिमहेश झील पर मंदिर स्थापित करवाया था। इस यात्रा के लिए फिटनेस टेस्ट भी अनिवार्य रूप से कराना पड़ता है,सेनजीत कसौधन दाऊ कैलाशी ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार ने स्वच्छता

बनाए रखने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को भी बहुत कड़ाई से लागू किया था। रजनीश बरनवाल का कहना था कि यात्रा कठिन जरूर है लेकिन हर बढ़ता कदम उत्साहित करता है। सुल्तानपुर पहुँचने पर दल में शामिल श्रद्धालुओं पवन कुमार साव, सेनजीत कसौधन दाऊ, रवि कसौधन, रजनीश बरनवाल, सिंपल बरनवाल, अजय रावत, अंकित अग्रहरि, शैलेंद्र अग्रहरी, सत्यम बरनवाल, दुर्गेश मोदनवाल, शारदा मोदनवाल का शंकर लाल कैलाशी, आलोक सागर, अमित दीपू आदि ने पुष्पवर्षा के साथ अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया।

'भाभी और भतीजी का कैरेक्टर, इसलिए भैया को..., देवर ने सुनाई भाई के कत्ल की कहानी

आर्यावर्त संवाददाता

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक महिला ने अपने ही पति को मार डाला। वो भी बेटी के साथ मिलकर। कारण था, दोनों के चाल चलन से पति परेशान था। वो दोनों को टोकता रहता था। इससे घर पर आए दिन विवाद होते थे। दोनों मां-बेटी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई जारी है।

मामला अजगैन कोतवाली क्षेत्र के सिंघनापुर गांव का है। यहां रहने वाले 46 साल के राजेश कुमार का शव गुरुवार अल सुबह पांच बजे घर के अंदर जीने के पास लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। मृतक की पत्नी कामिनी की सूचना पर पुलिस ने जांच की तो पत्नी ने शराब के नशे में जीने के पास गिरने से मौत की बात बताई। मगर पुलिस को शक हुआ, क्योंकि गले में और आंख में चोट के निशान थे। यही नहीं, रिश्तेदारों ने भी महिला पर ही शक जताया।

पुलिस ने तब आनन-फानन मां-बेटी को हिरासत में ले लिया। सूचना पर आए मृतक के ममेरे भाई संतोष बाबू ने पुलिस को बताया कि राजेश को अपनी बीवी और बेटा का चालचलन पसंद नहीं था। इसी के चलते वह विरोध करते थे। उनकी पत्नी कामिनी को उनसे अधिक मतलब नहीं था। वह सिर्फ पैसों के लिए राजेश के साथ थी। राजेश पर पांच बीघा जमीन बेचने का भी आरोप लगा रही थी। बेटी काजल के साथ मिलकर कामिनी आए दिन राजेश को पीटती भी थी। बेटे ने भी मां पर और बहन पर ही पिता की हत्या का शक जताया था। सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि के बाद मां-बेटी पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि शव दफन नहीं हो पाया। वह प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी कराई जाएगी।

संतोष बाबू ने बताया कि राजेश कुमार मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते थे। डेढ़ महीने पहले वह घर आए थे। पत्नी और बेटी का चाल-चलन सही न देख उन्होंने विरोध शुरू किया था। इस पर 29 जुलाई की रात पत्नी और बेटी ने राजेश को पीटा भी था। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे मलिहाबाद ले जाकर इलाज कराया था। बाद में उन्होंने फिर घर जाने की बात कही थी तो छोड़ दिया था।

चार बच्चों के पिता था राजेश कुमार

मृतक के बड़े बेटे आशीष को भी पिता के साथ हुई हरकत अच्छी नहीं लगी थी। इस पर छह दिन पहले उसने खुद मुंबई जाने की बात कहकर पिता को घर पर ही रोक दिया था। घटना की सूचना मिलने के बाद वह मुंबई से चला है। मृतक राजेश के चार बच्चों में आशीष, प्रिंस, बेटी काजल और सेजल हैं। पिता की मौत और मां और बहन पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब प्रिंस, काजल और सेजल पर परवरिश का संकट खड़ा हो गया है। अभी तक कोई भी रिश्तेदार उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस ही अभी उनका सहारा है।

जरूरतमंदों के लिए संजीवनी बना राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ

सुलतानपुर। समाजसेवा की असली मिसाल पेश कर रहा राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ पिछले तीन वर्षों से बिना किसी अवरोध के सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है। यह सेवा स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालय के मरीजों-तीमारदारों के साथ-साथ रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों तक निरंतर पहुँच रही है। इस पुनीत कार्य से न केवल भूखे पेटों को सहारा मिल रहा है बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता का संदेश भी जा रहा है। संघ के अध्यक्ष मेराज अहमद खान के संयोजन और वरिष्ठ समाजसेवी निज़ाम खान के मार्गदर्शन में यह अभियान प्रत्येक गुरुवार को संचालित होता है। निज़ाम खान का कहना है कि यह कार्य पूरी तरह जन सहयोग से संचालित है। सहयोगकर्ताओं की मदद से शुद्ध, पौष्टिक और गुणवत्ता वाला ताजा भोजन तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाता है।

दो बीवियां, तीन बच्चे, और तीसरी दुल्हन की एंट्री : लखनऊ के दूल्हे ने भिड़ाया ऐसा तिकड़म, शादी भी की और...

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। आपने अक्सर लुटेरी दुल्हनों के कई किस्से सुने होंगे। मगर लखनऊ का एक दूल्हा भी कुछ ऐसा ही निकला, जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दूल्हे की पहले से ही दो बीवियां हैं। फिर भी उसने तीसरी शादी की। उसके बाद कुछ ऐसा कर गया कि अब पुलिस दूल्हे को हर कहीं तलाश रही है। ताकि उसे अरेस्ट किया जा सके। दरअसल, दूल्हे ने शादी के बाद दुल्हन के घर से दो टू-व्हीलर चुरा लिए।

मामला महानगर थाने का है। यहां कुछ समय पहले एक महिला टीचर की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक युवक से हुई। युवक ने उसे अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में फंसाया। फिर बोला- मुझे अपना फोन नंबर दो, ताकि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकूं। युवती भी उसकी बातों में आ गई। उसने युवक को फोन नंबर दे दिया। फिर क्या था, दोनों ने जब बात करना शुरू किया तो ये सिलसिला आगे

बढ़ता ही चला गया।

फिर एक दिन युवक ने युवती से कहा- मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। युवती को भी वो युवक काफी पसंद था। इसलिए उसने शादी के लिए हां कर दी। दोनों ने फिर आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी की। उसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हनिया के यहां रहने लगा। मगर दुल्हन नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दूल्हा एक-एक करके दुल्हन के घर से दो स्कूटी लेकर भाग गया।

जब दुल्हन ने पाया कि दूल्हा घर पर नहीं है तो उसने उसे फोन किया। मगर मोबाइल बंद था। दुल्हन उसे तलाशने लगी। तब दुल्हन को पता चला कि दूल्हा को फर्जी था। उसने उसे धोखा देकर शादी की थी। दूल्हे की पहले से ही दो बीवियां और तीन बच्चे हैं। दूल्हे का मकसद सिर्फ दुल्हन के घर से चोरी करना था।

दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज

रोते-बिलखते फिर दुल्हन थाने में पहुंची। फिर यहां उसने दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बताया कि कैसे इंस्टाग्राम पर दूल्हे ने उसे फंसाया और शादी की। दुल्हन बोली- साहब! उसने मेरे साथ धोखा किया है। मैं चाहती हूं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले।

शातिर दूल्हे की तलाश जारी

महानगर थाने ने मामला दर्ज कर अब शातिर दूल्हे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा- हम जल्द ही दूल्हे को गिरफ्तार कर लेंगे। ये भी पता लगाया जा रहा है कि और कितनी महिलाओं को उसने अपना शिकार बनाया है। मामले में जांच जारी है।

डीएम के आदेश को ठेंगा, घोटालेबाजों को संरक्षण

» हैंडपंप रिबोर के नाम पर दुबेपुर ब्लॉक के चकरपुर गांव में 10 लाख रूपये से अधिक का घोटाला

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। दुबेपुर ब्लॉक के चकरपुर गांव में हैंडपंप रिबोर के नाम पर 10 लाख रुपये से अधिक के घोटाले की जांच जिलाधिकारी के आदेश पर भी नहीं शुरू हो सकी है। जबकि ग्रामीणों ने इस गंभीर मामले की शिकायत शपथपत्र के साथ जिलाधिकारी को सौंपी थी।

सूत्रों के अनुसार, जिलाधिकारी ने जांच का जिम्मा डीपीआरओ को सौंपा, लेकिन डीपीआरओ ने पारदर्शी जांच कराने के बजाय अपने चहेते और "घोटाले दबाने के माहिर" माने जाने वाले जिला उद्यान अधिकारी को जांच अधिकारी नामित कर दिया। हैरत की बात यह है कि आदेश जारी हुए महीनों गुजर जाने के बावजूद जिला उद्यान अधिकारी अब तक गांव जांच करने तक नहीं पहुंचे।

ग्रामीणों का आरोप है कि घोटाले में शामिल ग्राम प्रधान व जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। यही नहीं, इस तरह के हैंडपंप रिपोर्ट घोटाले का अंदेशा दुबेपुर ब्लॉक के अन्य गांवों में भी जताया जा रहा है, जहां लाखों-करोड़ों रुपये की बंदरबांट हुई होने की संभावना है।

'डीपीआरओ पर उठ रहे सवाल'

लोगों का कहना है कि डीपीआरओ खुद डीएम की शक्ति को नजरअंदाज कर किसी माननीय के इशारे पर घोटाले को दबाने में जुटे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि गांव-गांव में होने वाली इस तरह की बंदरबांट पर रोक लग सके।

'रात में कमरे में बुलाकर...' नर्स ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप, बोली–ऐसे हालात में कैसे नौकरी करें

आर्यावर्त संवाददाता

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से अस्पताल में एक महिला नर्स से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप अस्पताल के अधीक्षक पर लगा है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सरेनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का है, जहां पर तैनात एक महिला स्टॉफ नर्स ने अधीक्षक डॉ। राजेश गौतम पर छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप लगाया है।

पीड़िता का आरोप है कि अधीक्षक रात में उन्हें अपने कमरे में बुलाते हैं और वहां पर गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। विरोध करने पर न केवल अभद्रता की जाती है, बल्कि बार-बार फोन करके परेशान भी किया जाता है। नर्स ने कहा है कि अगर ऐसा ही

वातावरण रहा तो वह नौकरी जारी नहीं रख पाएगी। उसने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

आरोपी अधीक्षक पर सख्त कार्रवाई की मांग

पीड़िता की मांग है कि आरोपी अधीक्षक पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और महिला कर्मचारी को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। वहीं, जब इस विषय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ। नवीन चंद्रा से बात की गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उनका कहना था कि मामला गंभीर है और इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

क्या बोले आरोपी डॉक्टर?

एक ओर जहां पीड़िता इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। आरोपी अधीक्षक डॉ। राजेश गौतम ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि यह मामला बैठकर बातचीत से सुलझाया जा सकता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सरकारी दफ्तरों में महिला सुरक्षा की स्थिति कितनी कमजोर है। सवाल उठता है कि जब सरकारी दफ्तरों में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो खुले समाज और सड़कों पर उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

पीड़िता ने मांग की है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, तभी महिला कर्मचारियों में विश्वास पैदा होगा और वे बिना भय के अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगी।

ग्रामीणों की जिंदगी नरक बना रही है सूदखोरी

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोरों की बल्ले-बल्ले हो गई है। सरकारी बैंक होने के बावजूद गांवों में ये अवैध साहूकार गरीब और जरूरतमंदों को अपनी क्रूर शर्तों पर कर्ज देकर उन्हें बर्बादी के दलदल में धकेल रहे हैं। ये लोग जरूरतमंदों से 5फ से 10फ तक मासिक ब्याज वसूल रहे हैं, जो कि पूरी तरह अवैध है और 'मनी लेंडर्स एक्ट' के तहत स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध है।

सूदखोरों के मक्कारी और ठगी के शिकार गरीब, समय पर किश्त न चुका पाने पर जमीन और जेवर भी गंवा देते हैं। सूदखोर मानसिक प्रताड़ना की हदें पार कर देते हैं। कई मामलों में तो गरीबों ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन दोषियों के खिलाफ न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही प्रशासन ने सुध ली। यह एक ऐसा जटिल समस्या है जिसमें किसान/गरीब व्यक्ति जब सूदखोर महाजन के मकड़जाल में फंस जाता है तो ब्याज पर ब्याज का कर्ज उतारते वह बर्बाद हो जाता है। जबकि अनैतिक ब्याज कानूनन अपराध है। जिसे शासन व प्रशासन में बैठे जिम्मेदार भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। अवैध ब्याजखोरों के प्रति प्रशासन और शासन की चुप्पी इस गैरकानूनी धंधे को बढ़ावा दे रही है। बल्दीराय तहसील ही नहीं पूरे जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ,सूदखोरों का मकड़जाल मजबूती से फैला हुआ है। ब्याजखोरों के राजनैतिक और व्यक्तिगत प्रभाव के चलते प्रशासन की चुप्पी ,इस धंधे को और बढ़ावा दे रहे हैं। यदि अब भी शासन जाग जाता है और अवैध सूदखोरों की पहचान करके, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे तो गरीब लोगों को न्याय मिलेगा तो वहीं सरकार की ऐसे अपराधियों और अपराध पर शिकंजा कसने से पीड़ति लोग अनुचित प्रताड़ना से बच जाएंगे।

3 फर्जी पासपोर्ट, 2 थाई ID और बदला हुआ नाम... लखनऊ एयरपोर्ट से अरेस्ट हुई थाईलैंड की ब्लैकलिस्टेड महिला

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। यूपी के लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार सुबह इमीग्रेशन अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लैकलिस्टेड थाई नागरिक को हिरासत में लिया। महिला फर्जी पासपोर्ट के जरिए बैंकॉक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा जांच में उसके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। महिला का नाम थोंगफुन चायफा उर्फ दरिन चोकथनपट है।

अधिकारियों ने उसके पास से 3 फर्जी पासपोर्ट, 2 थाई आईडी, बोर्डिंग पास और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। थोंगफुन चायफा उर्फ दरिन चोकथनपट नाम की यह महिला पहले से ही भारत में यात्रा के लिए ब्लैकलिस्टेड थी। महिला को मार्च 2025 में एग्जिट परमिट पर भारत से भेजा गया था। इसके बाद वह 31 जुलाई 2025 को फर्जी

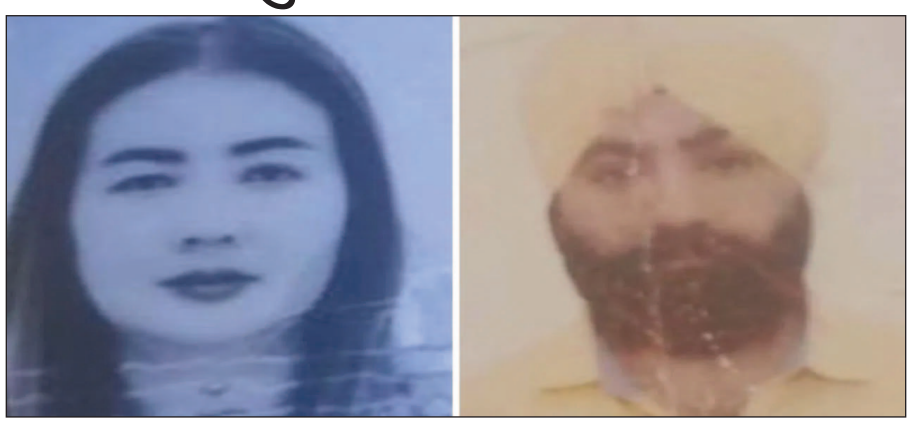

पासपोर्ट से रक्सौल बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर गई।

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ निवासी जसविंदर सिंह ने अपने साथियों नवेंदु मित्तल और शुवेंदु निगम की मदद से महिला के लिए कई फर्जी पासपोर्ट बनवाए। इमीग्रेशन अधिकारी के अनुसार, पकड़ी गई महिला ने अपना नाम डारिन चोकथनपत बताया और पासपोर्ट नंबर AD 2175735 प्रस्तुत किया। जांच में खुलासा हुआ कि यह वही महिला है जो जुलाई 2024 में भारत आई थी और थोंगफुन चयाफा नाम से यात्रा कर चुकी थी। वीजा उल्लंघन के कारण भारत सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था और मार्च 2025 में एक्जिट परमिट पर देश छोड़ना पड़ा था।

नेपाल के रास्ते भारत में ली थी एंट्री

पूछताछ में महिला ने माना कि जसविंदर सिंह नामक व्यक्ति ने उसे फर्जी पासपोर्ट दिलवाने में मदद की। पासपोर्ट में न सिर्फ उसका नाम बल्कि माता-पिता का नाम भी बदलकर दर्ज किया गया। इसके बाद 31 जुलाई 2025 को वह रक्सौल बॉर्डर से नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई और तब से जसविंदर सिंह के लखनऊ स्थित घर में रह रही थी।

पहले भी आ चुकी थी पुलिस की गिरफ्त में

इस महिला की गतिविधियों की जानकारी 13 अगस्त को ही इंटेलिजेंस एजेंसियों और एफआरओ लखनऊ तक पहुंच चुकी थी। उस समय पुलिस ने महिला और जसविंदर सिंह को हिरासत में लिया था, लेकिन बिना केस दर्ज किए उसे जाने दिया। यही लापरवाही अब फिर सवालों के घेरे में है।

अधर्म के रास्ते से बेहतर है मौत इमाम हुसैन ने दिया था पैगाम

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। वक़्फ़ इमामबाड़ा हयातनगर में ब्रस्पतिवार को रात 8 बजे मजलिस को खेताब करते हुये मौलाना डॉ कमर अब्बास रिज़वी ने कहा कि इमाम हुसैन ने शहादत देकर इतना बड़ा पैगाम दिया कि अधर्म के मार्ग पर चलने से बेहतर है मौत इमाम हुसैन शहीद हो कर भी ज़दिा है और अधर्मी शासक यज़ीद का नाम लेवा तक कोई नहीं है और मौलना ने अली अकबर की दर्दनाक शहादत का मंज़र बयान की। जिसे सुनकर मजलिस में बैठे लोग फूट फूट कर रोने लगे मजलिस के बाद शबीह ताबूत अली अकबर की ज़ियारत कराई गईं और मुल्क के मशहूर नौहाख्वान जनाब फैशल नावेद ने अली अकबर के हाल का दर्दभरा नौहा पढ़ा जिसे सुनकर लोग़ खूब रोये मजलिस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहें यह जानकारी कमेटी तमन्ना ए मूसा के अध्यक्ष क़ायम मेंहदी चाँद ने दीं।

गुस्से में पार्टनर से हो जाती है बहस? अपनाइए ये टिप्स और बचाइए अपना रिश्ता

रिश्ते में यह समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और प्यार का असली मतलब है एक-दूसरे की अपूर्णताओं को स्वीकार करना। इस लेख में जानिए पार्टनर के साथ होने वाली छोटी-बड़ी लड़ाइयों को कैसे हैंडल करें।

रिश्ता दो लोगों के बीच सिर्फ प्यार और रोमांस का नाम नहीं है, बल्कि इसमें समझ, धैर्य और एक-दूसरे को स्वीकार करने की ताकत भी शामिल होती है। जब दो अलग-अलग सोच और आदतों वाले लोग साथ आते हैं, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। कभी ये मतभेद छोटी-छोटी बातों पर होते हैं, जैसे किसी फिल्म का चुनाव, खाना बनाने का तरीका या फिर देर से मैसेज का जवाब। ऐसी नोकझोंक रिश्ते में ताजगी और वास्तविकता दोनों बनाए रखती है। असल परेशानी तब होती है जब इन छोटी-छोटी बातों को हम दिल से लगाकर बड़ी लड़ाई में बदल देते हैं।

छोटी-छोटी लड़ाइयां रिश्ते को कमजोर करने की बजाय मजबूत भी बना सकती हैं, बशर्ते उन्हें सही तरीके से संभाला जाए। इसके लिए जरूरी है पार्टनर की बात ध्यान से सुनना, इगो को किनारे रखना और गुस्से में जल्दबाज़ी से फैसले न लेना। रिश्ते में यह समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और प्यार का असली मतलब है एक-दूसरे की अपूर्णताओं को स्वीकार करना। इस लेख में जानिए पार्टनर के साथ होने वाली छोटी-बड़ी लड़ाइयों को कैसे हैंडल करें।

हर बहस को बड़ी लड़ाई न बनाएं

रिश्ते में छोटी-छोटी नोकझोंक होना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अक्सर हम इन्हें बड़ा रूप दे देते हैं। याद रखें, हर बहस का मतलब ब्रेकअप या दूरी नहीं होता। रिश्ते की मजबूती इसी में है कि आप छोटे-छोटे मतभेदों को प्यार और धैर्य से सुलझा सकें। यही हेल्दी रिलेशनशिप की असली पहचान है।

सुनना सीखें, सिर्फ बोलना नहीं

कई बार हम सिर्फ अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं और पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। रिलेशनशिप में छोटी-छोटी लड़ाइयों को सुलझाने का सबसे असरदार तरीका है ध्यान से सुनना। जब पार्टनर को लगेगा कि उसकी बातें मायने रखती हैं, तो बहस आधी खुद-ब-खुद खत्म हो जाएगी।

इगो को अलग रखकर करें बातचीत

छोटी-छोटी लड़ाइयों का सबसे बड़ा कारण होता है 'मैं सही हूँ' वाली सोच। अगर आप रिश्ते को लंबा चलाना चाहते हैं, तो इगो को दरवाज़े के बाहर छोड़कर बातचीत करें। 'सॉरी' कहना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते की मजबूती की निशानी है।

गुस्से में तुरंत फैसला न लें

बहुत से कपल्स गुस्से में तुरंत ब्रेकअप, अलग होने या चुप्पी साध लेने का फैसला कर लेते हैं। इससे रिश्ते कमजोर होते हैं। बेहतर होगा कि गुस्से के समय थोड़ा शांत होकर सोचें और फिर मिलकर समाधान निकालें।

लड़ाई के बाद की खामोशी

छोटी-छोटी लड़ाइयों के बाद सबसे जरूरी है रिश्ता फिर से पहले जैसा बनाना। एक प्यारी सी मुस्कान, गले लगाना या छोटा सा सरप्राइज, दोनों के बीच की खामोशी को तुरंत मिटा सकता है। रिश्ते की खूबसूरती इसी में है कि लड़ाई के बाद भी प्यार पहले से ज्यादा गहरा हो।

फैटी लिवर बढ़ा सकता है लिवर कैंसर का खतरा, समय रहते हो जाएं सावधान

फैटी लिवर की समस्या को अगर समय रहते कंट्रोल न किया जाए तो यह सिरोसिस और आगे चलकर लिवर कैंसर तक का कारण बन सकता है।

लिवर से संबंधित बीमारियों का खतरा सभी उम्र के लोगों में देखा जा रहा है। भारतीय आबादी में भी इसका जोखिम बढ़ गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक आजकल हर तीसरा भारतीय फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहा है। यह आंकड़ा हमें डराता भी है और सावधान भी करता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये खाना पचाने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, खून को साफ रखने और ऊर्जा बनाने का काम करता है। लेकिन जब लिवर की कोशिकाओं में चर्बी जमने लगती है, तो धीरे-धीरे यह अपनी ताकत खोने लगता है। इस स्थिति को फैटी लिवर रोग के रूप में जाना जाता है।

भारत में लिवर रोग एक गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जिसमें नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (एनएएफएलडी) और कई अन्य प्रकार के क्रोनिक लिवर रोग प्रमुख हैं। असली गेम-चेंजर नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, जो साइलेंटली एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले चुका है।

एम्स के एक अध्ययन में बताया गया है कि लगभग 38% भारतीय आबादी फैटी लिवर से प्रभावित है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि फैटी लिवर की समस्या कुछ स्थितियों में कैंसर का भी कारण बन सकती है?

फैटी लिवर और इसके कारण होने वाली दिक्कतें

भारत में हर साल लिवर की बीमारी से 2.68 लाख से अधिक मौतें दर्ज की जाती हैं, जो दुनियाभर में लिवर से संबंधित सभी मौतों का 18 प्रतिशत से अधिक है। चूंकि फैटी लिवर के मामलों में भी उछाल देखा जा रहा है ऐसे में कैंसर और इससे मौत का भी जोखिम बढ़ जाता है।

अध्ययनों से पता चलता है कि फैटी लिवर की समस्या को अगर समय रहते कंट्रोल न किया जाए तो यह सिरोसिस और आगे चलकर लिवर कैंसर तक का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, लिवर कैंसर के करीब 25-30% मामले फैटी लिवर से जुड़े होते हैं।

फैटी लिवर और कैंसर का खतरा

शोध बताते हैं कि जब लिवर में लगातार फैट और सूजन की स्थिति बनी रहती है, तो वहां की कोशिकाएं बार-बार क्षतिग्रस्त होती हैं । यह डीएनए को भी नुकसान पहुंचाता है और कोशिकाओं में असामान्य रूप से वृद्धि हो सकती है। यही स्थिति कैंसर का रूप लेती है।

अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार जिन्हें लंबे समय से मोटापा, डायबिटीज या शराब पीने की आदत रही हो उनमें फैटी लिवर और इसके कारण कैंसर होने का जोखिम अधिक रहता है।

मोटापे से ग्रस्त 90% तक लोगों में नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का जोखिम पाया जाता है। यह नॉन-अल्कोहल-रिलेटेड स्टीटोहेपेटाइटिस (एनएएसएच) नामक एक अधिक गंभीर स्थिति में बदल सकता है, जिसमें लिवर में सूजन और क्षति का खतरा रहता है। एनएएसएच के कारण सिरोसिस, लिवर फेलियर और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का भी खतरा रहता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर में कैंसर का सबसे आम प्रकार है।

फैटी लिवर से बचाव जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं इस तरह के जोखिमों को कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि फैटी लिवर से बचाव किया जाए। फैटी लिवर केवल शराब पीने से नहीं होता, बल्कि इसके और भी कई कारण हैं। मोटापा और पेट की चर्बी के शिकार लोगों के अलावा डायबिटीज की स्थिति भी लिवर में फैट बढ़ाने वाली हो सकती है।

गड़बड़ खानपान जैसे ज्यादा तली-भुनी चीजें, मीठा और पैक्ड फूड, शराब का सेवन और सेंडेंटरी लाइफस्टाइल भी नुकसानदायक है।

इन संकेतों को अनदेखा न करें

फैटी लिवर की शुरुआती स्टेज में अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखते। लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं, अगर आपको पेट में लगातार भारीपन या दाईं तरफ दर्द रहता है थकान, कमजोरी और भूख नहीं लगती तो इस बारे में चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अगर बार-बार पीलिया हो रहा है, उल्टी में खून या शौच का रंग काला हो गया है, इसके साथ अचानक से वजन कम होने लगा हो तो इसे अनदेखा न करें। ये लक्षण फैटी लिवर के कारण होने वाली गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकती हैं। लाइफस्टाइल सुधार से 70% मामलों में फैटी लिवर को कैंसर बनने से रोका जा सकता है।

स्किन पर गर्मी से निकल रहे हैं दाने तो क्या करें? ये घरेलू उपाय आएंगे आपके काम

यदि आपकी स्किन पर भी गर्मी के मौसम में दाने निकल रहे हैं तो कुछ घरेलू नुस्खे आजमाकर आप इस दिक्कत से राहत पा सकते हैं।

अगस्त का महीना चल रहा है, लेकिन मौसम का अंदाज किसी को समझ नहीं आ रहा। कभी तो भीषण गर्मी होती है, तो वहीं कभी इतनी तेज बारिश होती है, कि मौसम काफी ठंडा हो जाता है। इस बदलते मौसम की वजह से लोगों की स्किन पर घमौरी और छोटे-छोटे दाने निकलने लगते हैं।

ये दिक्कत ऐसी होती है कि अगर इसका ध्यान सही समय पर न रखा जाए तो डॉक्टर के पास जाने तक की नौबत आ सकती है। कई मामलों में तो कपड़े तक पहनना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिसको आजमाकर आप इस दिक्कत से राहत पा सकते हैं।

चंदन का लेप

हर भारतीय घर में चंदन काफी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल पूजा-पाठ में होता है। इसी चंदन का पेस्ट बनाकर अगर आप उसे स्किन पर आए दानों पर लगाएंगे तो इससे आपको खुजली और जलन से राहत मिलेगी। ये शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। इसका पेस्ट बनाते समय सफाई का ध्यान रखें। वरना आपको ही काफी दिक्कत हो जाएगी।

नीम का पानी

अगर आपके घर के आस-पास नीम का पेड़ लगा है तो इससे अच्छा उपाय आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए सबसे पहले नीम की पत्तियों को तोड़कर उसे अच्छी तरह से धो लें। पत्तियों को धोने के बाद उसे पानी में उबाल लें। अब चाहें तो इस पानी को ठंडा करके इससे स्नान करें। नहीं तो आप इस पानी को रुई की मदद से भी अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। ये फंगल इंफेक्शन से भी राहत पहुंचाती है।

बेसन और दही

जिस तरह से ये दोनों चीजें स्किन केयर में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक उसी तरह से 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट को स्किन पर आए दानों पर अप्लाई करें। 15 मिनट के बाद अपनी स्किन को साफ पानी से धोकर साफ कर लें। जहां बेसन आपकी स्किन को साफ करेगा, वहीं दही स्किन को ठंडक पहुंचाने का काम करेगा।

ये गलतियां भूल से भी न करें

यदि आपकी स्किन पर दाने निकल रहे हैं, जिनपर जलन और खुजली हो रही है तो गलती से भी ज्यादा टाइट कपड़े न पहनें।

यदि आपको ज्यादा पसीना आता है तो उसे हल्के कपड़े या फिर टिश्यू की मदद से लगातार साफ करते रहें।

दिन में दो बार ठंडे पानी से स्नान करें, ताकि त्वचा को ठंडक मिलती रहे।

इन बातों को गांठ बांध लें

जब तक स्किन पर निकले दाने पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक ढीले-ढाले कपड़े पहनें, जो शरीर के लिए हवादार रहें। खूब पानी, नींबू पानी, नारियल पानी पीएं। इसके अलावा अगर दाने बहुत ज्यादा हैं, पस निकल रहा है या तेज खुजली हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

अगर आपको भी चाहिए हर महीने पेंशन, तो इस सरकारी योजना में कर सकते हैं आवेदन

आज की इस दौड़ती-भागती जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसके पास आर्थिक समस्या न हो। इसके लिए एक बड़ा तबका नौकरी करता है और अपनी आजीविका चलाता है। यही नहीं, लोग अपने आज के खर्चों के अलावा आने वाले कल के लिए बचत भी करते हैं। इसके लिए लोग अलग-अलग जगहों पर निवेश भी करते हैं। यही नहीं, लोग अपनी पेंशन की व्यवस्था भी करते हैं। इसी क्रम में एक योजना है अटल पेंशन योजना जिसे केंद्र सरकार चलाती है।

मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और पेंशन का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि इस योजना के तहत पात्र लोगों को 60 वर्ष के बाद हर महीने 1 से 5 हजार रुपये महीने तक की पेंशन मिलती है। ऐसे में अगर आप भी इस अटल पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस सरकारी योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना क्या है और आप कैसे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...

क्या है अटल पेंशन योजना?

दरअसल, केंद्र सरकार अटल पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत 1 से 5 हजार रुपये तक की हर महीने पेंशन मिलती है और ये लाभ 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलता है। इस योजना के तहत लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद करना है।

कैसे जुड़े इस योजना से?

स्टेप 1

अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 60 वर्ष के बाद हर महीने पेंशन प्राप्त हो, तो इसके लिए आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक की ब्रांच में जाना है

यहां जाकर आपको संबंधित अधिकारी से मिलना होता है, ये वो अधिकारी होते हैं जो इस योजना को देखते हैं

स्टेप 2

फिर अधिकारी आपकी केवाईसी करते हैं

इसके बाद आपको योजना का पेंशन प्लान (1,2,3,4 या 5 हजार रुपये महीने की पेंशन) चुनने को कहा जाता है

अब जो प्लान आप चुनते हैं उसे आपके बैंक खाते से लिंक कर दिया जाता है

फिर हर महीने आपके बैंक खाते से प्रीमियम कट जाता है

क्या लाभ मिलता है?

अटल पेंशन योजना में आपको हर महीने 1 से 5 हजार रुपये महीने की पेंशन 60 वर्ष के बाद मिलती है। दरअसल, आपको योजना से जुड़ने के बाद अपनी उम्र के हिसाब से प्रीमिमय देना होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये का प्रीमियम देना होता है। इसी तरह अलग-अलग उम्र के हिसाब से अलग-अलग प्रीमियम होता है। वहीं, जिन लोगों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होती है सिर्फ वे ही इस योजना से जुड़ सकते हैं।

लगातार गिर रहे सोने-चांदी के दाम, शादी और त्योहार की खरीदारी होगी आसान

मुंबई, एजेंसी। भारतीय वायदा और सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिली। लगातार कई दिनों से जारी गिरावट के बाद अब बाजार में मिश्रित रुख नजर आ रहा है। जहां सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, वहीं चांदी के दामों में हल्की बढ़त देखी गई है।

सुबह 11:15 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 99,080 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 99,304 से 224 कम है। वहीं, चांदी का दाम 1,12,704 प्रति किलो पर पहुंच गया, जो पिछले स्तर से 151 ज्यादा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं देखी गई। स्पॉट गोल्ड 0.1 प्रतिशत गिरकर $3,341.93 प्रति औंस पर रहा। इसी तरह, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी 0.1 प्रतिशत टूटकर $3,384.40 प्रति औंस पर बंद हुए।

निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी नीतियों पर है। वायोमिंग के जैक्सन होल में 21 से 23 अगस्त तक होने वाले वार्षिक आर्थिक सिम्पोजियम में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के भाषण पर बाजार की दिशा निर्भर करेगी।

कमोडिटी विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सोना कंसोलिडेशन फेज में है। अगर फेड ब्याज दरों में थोड़ी भी कटौती करता है तो सोना $3,400 प्रति औंस तक जा सकता है। वहीं, अगर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कीमतें $3,300 तक गिर सकती हैं।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार को लगातार पांचवें दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 222 टूटकर 98,946 प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरेट सोना घटकर 90,635 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इसी तरह 18 कैरेट सोना भी 74,210 प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी में भी तेज गिरावट देखने को मिली और बीते 24 घंटे में यह 2,431 टूटकर 1,11,194 प्रति किलो पर आ गई।

लगातार गिरते दामों से सर्राफा बाजार में ग्राहकों की हलचल बढ़ने लगी है। शादी और त्योहारों के सीजन को देखते हुए सोने-चांदी की खरीदारी में तेजी आने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा स्तर ग्राहकों के लिए निवेश और खरीदारी का सुनहरा अवसर है।

एलन मस्क पर धोखाधड़ी का आरोप, अदालत में करना होगा मुकदमे का सामना

नई दिल्ली, एजेंसी। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क एक नए विवाद में फंस गए हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने मस्क को एक मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया है। यह मुकदमा एक ऐसी योजना से जुड़ा है, जिसमें लोगों से अमेरिकी संविधान का समर्थन करने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करवाए गए और इसके बदले 10 लाख डॉलर जीतने का लालच दिया गया था।

वादियों का आरोप है कि मस्क और उनकी राजनीतिक समिति अमेरिका पीएसी ने यह प्रचार किया कि अगर लोग याचिका पर हस्ताक्षर करेंगे तो उनमें से कुछ को लॉटरी के जरिए हर दिन 10 लाख डॉलर का इनाम मिलेगा। लेकिन बाद में पता चला कि विजेताओं का चयन पहले से ही किया गया था। यानी यह योजना पारदर्शी नहीं थी और लोगों को धोखे में रखकर उनकी जानकारी इक_ी की गई।

एरिजोना की रहने वाली जैकलीन मैकएफर्टी नामक महिला ने यह मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि उन्हें और अन्य मतदाताओं को नाम, पता, ईमेल और फ़ोन नंबर जैसी निजी जानकारी देनी पड़ी। उनका आरोप है कि यह जानकारी चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल की गई।

मस्क और उनकी समिति ने अदालत में कहा कि यह कोई अवैध लॉटरी नहीं थी। उनका दावा है कि जिन लोगों को 10 लाख डॉलर दिए गए, उनसे अमेरिका पीएसी का प्रवक्ता बनने और काम करने की उम्मीद की गई थी। यानी यह राशि एक तरह की भुगतान की गई भूमिका थी, न कि कोई इनाम। मस्क का कहना है कि उन्होंने किसी को गुमराह नहीं किया।

लेकिन टेक्सास के जिला न्यायाधीश रॉबर्ट पिटमैन ने कहा कि पीएसी के कई बयानों से यह जाहिर होता है कि यह योजना सचमुच एक इनाम या लॉटरी जैसी थी। ऐसे में आम लोग यह मान सकते थे कि वे लॉटरी में हिस्सा ले रहे हैं। अदालत ने माना कि वादी का दावा विश्वसनीय है और मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए।

गौरतलब है कि एलन मस्क ने 2024 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान का समर्थन करने के लिए यह पीएसी बनाया था। माना जा रहा है कि यह मामला अब राजनीतिक रूप से भी बड़ा मुद्दा बन सकता है।

अमेरिका 5.5 करोड़ विदेशियों के वीजा रिव्यू करेगा... इसका 52 लाख भारतीयों पर क्या असर होगा?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में रह रहे 5.5 करोड़ से ज्यादा विदेशी नागरिकों के वीजा की समीक्षा की जा रही है। इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशियों का वीजा रद्द किया जाएगा और उन्हें उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस जांच का असर 52 लाख भारतीयों पर भी पड़ेगा। अमेरिका में 50 लाख से ज्यादा भारतीय नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर हैं। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने 2024 में लगातार दूसरे साल 10 लाख से ज्यादा गैर-अप्रवासी वीजा जारी किए थे।

अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, आपराधिक, आतंकी या अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और वीजा अवधि से ज्यादा समय तक रुकने पर कार्रवाई की जाएगी। विदेशी नागरिकों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि वीजा होल्डर के देश में उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं शुरू हुई है।

2025 में 2 लाख से ज्यादा अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट किया

अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने 2025 में 2 लाख से ज्यादा अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट किया है। इनमें से 75% अप्रवासियों को आपराधिक मामलों में अरेस्ट किया गया था। डिपोर्ट किए गए कुल लोगों में 35-40% नागरिक मेक्सिको के थे। इन्हें डिपोर्ट करने का कारण था- अमेरिका में अवैध एंट्री, वीजा अवधि से ज्यादा समय तक रुकना या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना। 20 जनवरी से 22 जुलाई, 2025 के बीच 1,703 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। इनमें पंजाब के 620, हरियाणा के 604 और गुजरात के 245 थे। हालांकि इनमें से उन भारतीयों की संख्या नहीं सामने आई, जो वीजा होल्डर थे। इनमें से कई भारतीयों की वीजा अवधि खत्म हो चुकी थी और बहुतों के डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई थी। अमेरिका में करीब 18 हजार अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की गई है, जिन्हें वापस भारत भेजा जाना है।

US में एशियाई मूल की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारतीय

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाली एशियाई मूल की दूसरे सबसे बड़ी आबादी भारतीय है। भारतीय अमेरिकी अब अमेरिका में कुल एशियाई आबादी का लगभग 21% हिस्सा हैं। माइग्रेशन ट्रेंड और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से अमेरिका में भारतीयों की आबादी पिछले 2 दशक में बढ़ी है। साल 2000 से भारतीय आबादी में 174% का इजाफा हुआ है। 2000 में यहां भारतीय प्रवासियों की संख्या 13 लाख थी, जो 2023 तक बढ़कर 32 लाख हो गई है। इस प्रवासी आबादी में से 60% लोग 10 साल से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रहे हैं। 51% ने अमेरिकी नागरिकता हासिल कर ली है।

कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के 9।60 लाख लोग

कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इनकी आबादी करीब 9.6 लाख है। टेक्सास में 5.7 लाख, न्यू जर्सी में 4.4 लाख, न्यूयॉर्क में 3।9 लाख और इलिनॉय में 2.7 लाख लोग भारतीय मूल के निवासी हैं। न्यूयॉर्क में 7.1 लाख, डलास में 2.7 लाख और सैन फ्रांसिस्को में 2.6 लाख लोग भारतीय मूल के निवासी हैं।

साउथ अमेरिका में भूकंप के तगड़े झटके, चिली में सुनामी की चेतावनी जारी

वॉशिंगटन, एजेंसी। साउथ अमेरिका में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7।5 मापी गई है। इतनी तीव्रता के भूकंप में सुनामी आने तक की चेतावनी दे दी जाती है। USGS के अनुसार, इस भूकंप की गहराई 10.8 किलोमीटर बताई जा रही है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार ये भूकंप भारतीय समयानुसार 07 बजकर 46 मिटने 22 सेकंड पर आया है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) ड्रेक पैसेज क्षेत्र में एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 8 से घटाकर 7।5 कर दी गई। हालांकि अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने ड्रेक पैसेज भूकंप के बाद कोई चेतावनी जारी नहीं की है। आमतौर पर इतने तेज झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया जाता है। केवल चिली में ही सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका के जिस क्षेत्र में भूकंप में झटके महसूस हुए हैं, वह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यह दक्षिण अमेरिकी और अंटार्कटिक टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है। यूएसजीएस के आंकड़ों के अनुसार, भूकंप का केंद्र 10.8 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि, जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी है।

हालांकि, अभी किसी बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आई है। ड्रेक पैसेज, जो अपने खतरनाक समुद्री मार्ग और तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां आए दिन महसूस की जाती हैं।

उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन, पीएम मोदी ने ऐसे किया याद

ब्रिटेन। भारत में जन्मे ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार शाम लंदन में निधन हो गया। कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। पॉल की उम्र 94 साल थी। पीएम मोदी ने पॉल के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। पॉल ब्रिटेन की कपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे।

पॉल के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "स्वराज पॉल के निधन से अत्यंत दुःखी हूं। ब्रिटेन में उद्योग, परोपकार और जनसेवा में उनके योगदान और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके अटूट समर्थन को सदैव याद रखा जाएगा। मुझे हमारी अनेक मुलाकातें याद आती हैं।" पीएम मोदी ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की।

जलांधर में जन्में पॉल के पास कई अरबों की संपत्ति है। जानकारी के अनुसार पॉल की अनुमानित संपत्ति 2 अरब पाउंड है। इनकी इनकम सोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा स्टील और इंजीनियरिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय कंपनी कपारो समूह से आता है। कपारो कंपनी का मुख्यालय लंदन में है और वह 40 से ज्यादा जगहों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इस कंपनी का संचालन यूके, उत्तरी अमेरिका, भारत और मध्य पूर्व में है। कपारो समूह के निदेशक उनके बेटे आकाश पॉल हैं।

स्वराज पॉल ने 1975 में भारत और ब्रिटेन के बीच एक बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए इंडो-ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने इस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। साल 1983 में भारत सरकार ने पॉल को पद्म भूषण से सम्मानित किया था।

पॉल का जन्म जालंधर में हुआ था। उनकी छोटी बेटी कैंसर से पीड़ित थी, जिसके ईलाज के लिए वह 1960 में ब्रिटेन चले गए थे। इलाज कराने के वावजूद चार साल की उम्र में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। जिसके बाद उन्होंने एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में अंबिका पॉल फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से दुनिया भर के बच्चों और युवाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लाखों डॉलर दान किए। पॉल ने चार साल की अपनी छोटी बेटी को खोने के बाद 2015 में अपने बेटे अंगद और 2022 में अपनी पत्नी अरूणा को भी खो दिया। परिवार को खोने के बाद उन्होंने उनके नाम पर कई सारी संस्थाओं का उद्घाटन किया, जिसके जरिए वह लोगों की भलाई का काम करते थे।

पानी से लेकर खुले आसमान तक...1 मिनट में ईरान ने दागीं 11 मिसाइलें

यरुशलम, एजेंसी। इजराइल के साथ 12 दिन चले युद्ध के बाद ईरान की नेवी ने पहली बार सैन्य अभ्यास किया है। स्टेट टीवी प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास का नाम सस्टेनेबल पावर 1404 दिया गया है। नौसैनिक अभ्यास के दौरान ईरानी नौसेना ने महज 1 मिनट में 11 मिसाइलें दागीं।

ये मिसाइलें ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री लक्ष्यों पर दागी गईं। 12 दिनों के युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था और कई परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया था। ऐसे में ये सैन्य कवायद ईरान के लिए अपनी सैन्य ताकत दिखाने और दुश्मनों को चेतावनी देने की कोशिश मानी जा रही है।

नौसेना ने दिखाई मारक क्षमता

राज्य टीवी ने बताया कि ईरानी नौसेना के युद्धपोत आईआरआईएस सबलान और आईआरआईएस गनावेह ने नासिर और कादिर क्रूज मिसाइलें दागीं, जो अपने लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक लगीं। इसके अलावा तटीय बैटरियों से भी मिसाइलें छोड़ी गईं और ड्रोन के जरिए समुद्री लक्ष्यों पर हमला किया गया। नौसेना की यह कवायद ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में फैले क्षेत्र में की गई।

रूस के साथ अभ्यास के बाद ईरान का संदेश

गौर करने वाली बात ये है कि पिछले महीने ही ईरान और रूस ने कसारेक्स 2025 नाम से संयुक्त अभ्यास किया था। अब ईरान ने दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में अकेले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कवायद केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इजराइल को यह संदेश है कि ईरान अब भी जवाबी हमले की स्थिति में है।

परमाणु वार्ता पर ठंडा रुख

इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ चल रही परमाणु वार्ताओं को स्थगित कर दिया है। हालांकि, ईरान ने यह भी स्पष्ट किया कि वह संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ेगा। AP की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादेह ने कहा कि देश ने अपनी सेनाओं को नई मिसाइलों से लैस कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुश्मन की किसी भी नई साहसिक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

एमसीयू सत्रारंभ कार्यक्रम 'अभ्युदय' का समापन

ऐसी कहानियां लिखें जो मनोरंजन करें: विपुल के. रावल

भोपाल। सिनेमा की विभिन्न विधाओं में लिखने वाले लेखक देश को देखने और समझने के बाद ही अलग-अलग विषयों का समावेश कहानियों में करते हैं। हमारे देश में कहानियों और उनके विषयों की कोई कमी नहीं है। समाज में अलग-अलग दौर में फिल्मों की कहानियां कैसे लिखी गई हैं, इसे पिछले अनेक दशकों की फिल्मों को देखकर समझा जा सकता है। यह विचार आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के 'अभ्युदय' के अंतिम दिन 'रुस्तम' तथा 'इकबाल' जैसी चर्चित फिल्मों के पटकथा लेखक श्री विपुल के. रावल ने व्यक्त की। सत्रारंभ के अंतिम दिन वरिष्ठ पत्रकार श्री अनंत विजय, श्री बृजेश कुमार, श्री बालकृष्ण एवं सुश्री अदिति राजपूत ने विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों को सम्बोधित किया।

पटकथा लेखक श्री रावल ने भारतीय फिल्म उद्योग और वैश्विक सिनेमा के विकास की यात्रा पर चर्चा करते हुए फिल्म लेखन के क्षेत्र में आ रहे महत्वपूर्ण बदलावों को रियल लाइफ से जुड़े विषयों की कहानियों के साथ प्रस्तुत करते हुए लेखन एवं तकनीक के अन्तरसम्बन्धों पर चर्चा की। सत्र में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय ने कहा कि फिल्मों की कहानियां हमारी भावनाएं ही होती हैं। अगर हम गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सिनेमा की अधिकतर कहानियों में रामकथा की प्रेरणा होती है, क्योंकि रामकथा हमारे मन में रची-बसी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जन माध्यमों में आज फिल्म समीक्षा किसी फिल्म की व्याख्या बनकर रह गई है, उसमें विश्लेषण एवं विवेचना का अभाव स्पष्ट झलक रहा है। विद्यार्थियों को इसे समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि फिल्म रिव्यू राइटिंग के लिए कहानी में डीप डाइव करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि लोक की विराट जानकारी अगर हमें होगी तो बेहतरीन समीक्षाएं लिख सकेंगे।

एक अन्य सत्र में नेटवर्क 18 के वरिष्ठ संपादक डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने कहा कि तीन दशक पहले प्रिंट रेडियो का दौर था। उस समय टीवी पर महज कुछ समाचार बुलेटिन आते थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से जिस तरह डिजिटल का दौर शुरु हुआ उसमें प्रिंट मीडिया ने भी खुद को री-इन्वेंट किया और कन्वर्जेंस के हिसाब से खुद को अनुकूल किया। श्री सिंह ने कहा कि आज डिजिटल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है और इसने दूसरे माध्यमों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी है। अपने संपादन में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल का बाजार बहुत बढ़ेगा इसके साथ ओरिजिनल कंटेंट की मांग बढ़ेगी, अतःविद्यार्थी अपनी स्किल्स को बेहतर करने पर ध्यान दें।

इस सत्र के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार श्री बालकृष्ण ने मीडिया की विश्वसनीयता और ब्रॉडकास्टिंग पर अपने वक्तव्य में बताया कि किस तरह गलत सूचनाओं ने मीडिया में फैक्ट चैकिंग की मांग बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि किस तरह डिजिटल फ्रॉड देश भर में बढ़ रहे हैं। अपने व्याख्यान में उन्होंने मीडिया में विजुअल इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट चेकिंग पर बात करते हुए युवा तकनीक के साथ जुड़े रहें। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा एवं एनडीटीवी की एंकर अदिति राजपूत ने कहा कि मीडिया आज एक शक्तिशाली उपकरण है इसमें समाज को परिवर्तन करने की शक्ति है पर निश्चित तौर पर इसके कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अध्ययन पर जोर देने और नए कौशल सीखने की बात कही।

सेंसर टेक्नालॉजी पर अपनी बात रखते हुए ड्रोन टेक्नालाजी विशेषज्ञ चिराग जैन ने कहा कि मीडिया क्षेत्र से जुड़ी तकनीक का बेहद विकास हुआ है। पिछले कुछ दशकों में यह यात्रा प्रिंट मीडिया से होती हुए बेहरीन कैमरों और ड्रोन तकनीक तक विस्तृत हो गई है। ड्रोन तकनीक का समाज में उपयोग बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने अपने स्टॉर्टअप से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया। इस सत्र में उपस्थित अधिवक्ता शिखा छिब्बर ने भारतीय न्याय संहिता के नवीन पहलुओं पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य हर आम आदमी को न्याय देना है। उन्होंने बताया कि मीडिया के विद्यार्थियों के लिए नए कानूनों और उनके प्रावधानों का जानना बहुत जरूरी है।

विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा और वर्तमान में कालिंदी कॉलेज, नई दिल्ली की एसोशिएट प्रोफेसर डॉ. निधि अरोड़ा ने विश्वविद्यालय से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।उन्होंने कहा कि सफलता हमेशा आपका साथ देगी जब आप पूरी सामर्थ्य से उसे करेंगे। सिनेमा अध्ययन विभाग की पूर्व छात्रा और फिल्मकार सरिता चौरसिया ने फिल्म की दुनिया में कॅरियर कैसे शुरू करना और विश्वविद्यालय से जुड़े अपने अनुभवों पर अपने विचार रखे।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक पांडे ने कहा कि अधिकार एवं कर्तव्य एक साथ होते हैं, सत्य को समाज के सामने बिना किसी रंग के रखना पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के धर्म का पालन करना पत्रकारों का उत्तरदायित्व है इस अवसर पर कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि हमारे जीवन में कदम कदम पर हमें चौंकाता है। जीवन चमत्कृत करने वाली कई घटनाओं से भरा हुआ होता है। उन्होंने कहा कि सत्रारंभ में आए विशेषज्ञों के दिए गुरु मंत्र विद्यार्थियों के लिए जीवन भर काम आने वाले हैं। उन्होंने आह्वान किया कि आगामी 20 वर्षों में देश स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे करेगा और इस दौरान विकसित भारत का स्वप्न युवा विद्यार्थियों के योगदान से ही पूरा हो सकता है।

सत्रारंभ के तीसरे दिन सिनेमा अध्ययन विभाग के सत्र के दौरान वर्ष 2025 में फिल्म प्रोडक्शन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उत्सव ठाकुर को स्व. श्री अनिल चौबे स्मृति पदक एवं 21000 रुपये की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर श्रीमती आराधना चौबे उपस्थित थीं। विभिन्न सत्रों का संचालन डॉ. गजेन्द्र अवास्या, डॉ. सुनीता द्विवेदी, श्री राहुल खड़िया द्वारा किया गया। इस दौरान विभागाध्यक्ष प्रो. पवित्र श्रीवास्तव, डॉ. मोनिका वर्मा, प्रो. मनीष माहेश्वरी एवं समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षक एवं अधिकारी उपस्थित थे। अंत में आभार विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रोफेसर पी. शशिकला ने किया।

ब्लैक ड्रेस में नजर आईं उर्फी जावेद, हाथ पर चोट के निशान ने खींचा ध्यान; देखें वायरल वीडियो

उर्फी जावेद अपने अतरंगी अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर हैं। हाल ही में वह एक अलग तरह की ब्लैक ड्रेस में स्पॉट हुईं। पैपराजी को पोज देते हुए उनकी हाथ पर एक चोट का निशान नजर आया। आखिर क्या हुआ उर्फी जावेद को?

'ट्रेटर्स' जैसे रियलिटी शो को जीतने के बाद उर्फी जावेद अपने पुराने काम में बिजी हो गईं। वह अतरंगी किस्म की ड्रेस पहनकर मुंबई में नजर आती हैं और पैपराजी भी तब-जब इस इंफ्लुएंसर की तस्वीरें क्लिक करते दिखाई देते हैं। हाल ही में उर्फी जावेद एक ब्लैक ड्रेस की क्रिएटिव ड्रेस में दिखीं। लेकिन ड्रेस ज्यादा ध्यान उर्फी के हाथ की चोट ने खींचा है। उर्फी का चोट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

हाथ पर नजर आया लाल रंग का चोट जैसा निशान

वायरल वीडियो में उर्फी गाड़ी से निकलती हैं तो एक ब्लैक ड्रेस में नजर आती हैं, जो अलग ही ढंग से बनी थी। वह मुस्कुराते हुए पैपराजी को पोज देती हैं। इस बीच अचानक हाथ पर लाल रंग का निशान नजर आता है। देखकर लगता है कि यह चोट या जलने का निशान है।

यूजर्स ने किया ड्रेस को लेकर ट्रोल

सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उर्फी के इस वीडियो पर रिएक्शन दिया है। एक यूजर लिखता है, 'इस ड्रेस को क्या नाम दूं, साड़ी या अधूरी साड़ी।' एक अन्यू यूजर ने कमेंट लिखा, 'ये ड्रेस है?' जहां कुछ लोगों ने उर्फी की ड्रेस पर तंज कसा, वहीं कुछ यूजर्स ने फायर इमोजी उर्फी के लिए शेयर किए।

कई रियलिटी शो कर चुकी है उर्फी जावेद

उर्फी जावेद के करियर की बात करें तो पिछले साल उनकी लाइफ पर एक रियालिटी शो 'फॉलो कर लो यार' बना था। इस साल वह शो 'एंगेज्ड रोका या धोखा' को होस्ट करती दिखीं। हाल ही में रियालटी शो 'द ट्रेटर्स' में नजर आईं। सोशल मीडिया पर तो उर्फी एक्टिव रहती ही हैं।

पराधा का ट्रेलर रिलीज, पर्दे पर दिखेगी गांव की कहानी, 22 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

साउथ एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पराधा' को लेकर सुर्खियों में हैं। इसका डायरेक्शन प्रभु वेणुगोपाल ने किया है। रविवार को अनुपमा परमेश्वरन ने सोशल मीडिया पर मूवी का ट्रेलर शेयर किया और साथ ही कहा कि 'पराधा' उनके लिए एक सपने की तरह है। यह मूवी इस महीने थिएटर्स में दस्तक देगी।

फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि सुब्बू एक ऐसे गांव से हैं, जहां महिलाओं को पर्दा करना पड़ता है। एक दिन सुब्बू अचानक गायब हो जाती है और पता चलता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। गांव वाले मानते हैं कि सुब्बू की वजह से उनके गांव पर देवी का श्राप लगा है, इसलिए वे उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं।

कहानी आगे इस बात को दिखाती है कि कैसे दो शहर की महिलाएं सुब्बू के साथ खड़ी होती हैं और उनकी मदद से वह फिर से अपनी जिंदगी में मजबूती से खड़ी होती है। यह फिल्म महिला सशक्तिकरण, दोस्ती और हिम्मत की प्रेरणादायक कहानी है। फिल्म में अनुपमा सुब्बू नाम की लड़की का किरदार निभा रही है।

फिल्म को प्रसिद्ध जोड़ी राज और डीके ने मिलकर तैयार किया है। राज और डीके 'द फैमिली मैन' सीरीज के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का निर्माण विजय डोंकडा, श्रीनिवासुलु

पीवी, और श्रीधर मक्कुवा ने मिलकर अनंदा मीडिया कंपनी के बैनर तले किया है। अनुपमा परमेश्वरन के अलावा, फिल्म में दर्शन राजेंद्रन और संगीता भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। यह मूवी 22 अगस्त को रिलीज होगी।

इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म 'पराधा' का ट्रेलर शेयर करते हुए अनुपमा परमेश्वरन ने लिखा, 'पराधा मेरे लिए एक सपने की तरह है। यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैंने इसमें पूरी मेहनत और लगन से काम किया है। फिल्म को मैंने एक तरीके से जीया है।'

अनुपमा ने फिल्म की टीम का धन्यवाद करते हुए लिखा, 'मैं हर उस व्यक्ति की बहुत आभारी हूं जिसने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया और मेरी मदद की। मैं टीम का भी धन्यवाद करती हूं। मैं चाहती हूं कि भारी संख्या में लोग इस फिल्म की कहानी मेरे साथ देखें। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सबके दिल को भी उतना ही छू जाएगी जितना मेरे दिल को छू गई है। थिएटर में मिलते हैं।'

सत्यराज की एक्शन ड्रामा त्रिबंधरी बर्बरीक का दिमाग हिला देने वाला ट्रेलर रिलीज

सत्यराज, जो अपनी गतिशील स्क्रीन उपस्थिति और पैक्ड शूटिंग शेड्यूल के लिए जाने जाते हैं, एक अभूतपूर्व प्रोजेक्ट के लिए कमर कस रहे हैं, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया है, एक गहन एक्शन ड्रामा, पौराणिक तत्वों से भरपूर, जिसका शीर्षक त्रिबंधारि बर्बरीक है। अपनी तरह के पहले सिनेमाई अनुभव के रूप में प्रचारित, इस फिल्म ने पहले ही अपने अनूठे आधार और हड़ताली प्रचार सामग्री के साथ महत्वपूर्ण चर्चा पैदा कर दी है। टीज़र और साउंडट्रैक की शुरुआती झलक के अनावरण से, त्रिबंधारि बर्बरीक ने लगातार प्रत्याशा का निर्माण किया है। बड़े पैमाने पर ट्रैक इस्किथडी उस्किथडी, विशेष रूप से वायरल हुआ। मोहन श्रीवत्स के निर्देशन में, फिल्म पौराणिक भव्यता और हार्दिक कहानी कहने का एक अनूठा मिश्रण पेश करने का वादा करती है। वानरा सेल्युलाइड के बैनर तले विजयपाल रेड्डी आदिधला द्वारा निर्मित, मारुति टीम प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हुए, फिल्म का ट्रेलर आज लॉन्च किया गया है।

भगवान कृष्ण और बर्बरीक के बीच धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत युद्ध पर विचारोत्तेजक संवाद, ट्रेलर की शुरुआत को चिह्नित करता है। जैसे-जैसे दृश्य वर्तमान समय में बदलते हैं, हम एक सौम्य दादा को देखते हैं, जिसका किरदार सत्यराज ने निभाया है, जो अपनी प्यारी पोती के रहस्यमय ढंग से गायब होने से व्यथित है। यह पीड़ा उसके भीतर एक प्राचीन, बर्बरीक की आत्मा को प्रज्वलित करती है, क्योंकि वह धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के मिशन पर निकल पड़ता है।

मोहन श्रीवत्स ने पौराणिक कथाओं को एक मनोरंजक वर्तमान कथा में पिरोकर एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। सत्यराज ने एक कमज़ोर दादा और एक दिव्य योद्धा के बीच सहजता से बदलाव लाते हुए एक सशक्त अभिनय किया है।

उदय भानु खलनायक की भूमिका में दमदार प्रभाव छोड़ते हैं, जबकि सत्यम राजेश, वशिष्ठ एन. सिम्हा और सांची राय एक सम्मोहक कलाकार हैं। कुशेंद्र रमेश रेड्डी के दृश्य समृद्ध और भावपूर्ण हैं, जो इन्फ्यूजन बैंड के ज़बरदस्त बैकग्राउंड स्कोर से मेल खाते हैं।

वानर सेल्यूलॉइड के ठोस उत्पादन मूल्यों के साथ, त्रिबंधारी बर्बरीक एक नए तरीके से भावना, पौराणिक कथाओं और कार्रवाई का एक आदर्श मिश्रण पेश करने का वादा करता है।

यह फिल्म 22 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार हो रही है और इस मनमोहक ट्रेलर के साथ इसकी चर्चा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com